सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 219, नई दिल्ली । शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 *भगवान वाल्मीकि ने शिक्षा को समाज की तरक्की का मार्ग बताया

06 प्रतिदिन कुछ पढ़ना तेज़ दिमाग की कुंजी

08 जम्मू-कश्मीर के नये वजीरे ए आला व चुनौतियां।

दिल्ली परिवहन विभाग में नए विशेष परिवहन आयुक्तों का आगमन

NEW MD DTC Sachin shinde IAS 2008

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग में आसीन विशेष परिवहन आयुक्त के पद पर कार्यरत शहज़ाद आलम की जगह तत्काल प्रभाव से सचिन शिंदे का आगमन।

आदेश के अनुसार सचिन शिंदे जो अब तक एडिशनल कमिश्नर एमसीडी के पद पर कार्यरत थे को डीटीसी के एमडी के साथ विशेष परिवहन आयुक्त का पद पर कार्यरत किया गया है। आदेश के अनुसार सचिन शिंदे तत्काल कार्य भार संभाल कर शहज़ाद आलम को उनके पद से मुक्त करेंगे।

शिल्पा शिंदे को एमडी डीटीसी और विशेष परिवहन आयुक्त से मुक्त करके सीईओ दिल्ली जल बोर्ड का कार्य भार सौंपा गया है।

विशेष परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) के पद का कार्यभार अब संजीव कुमार मित्तल संभालेंगे यह पहले एमडी डीटीडीसी के पद पर कार्यरत थे।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
SERVICES DEPARTMENT: SERVICES-I BRANCH
DELHI SECRETARIAT: 5TH LEVEL: B-WING
I.P. ESTATE: NEW DELHI
http://services.delhigovt.nic.in
Tel: 011 – 23392038

F.No.8/17/2023/S.I Dated: 17.10.2024

ORDER No. 334

Hon'ble Lt. Governor, Delhi is pleased to order transfer/posting in respect of following IAS officers, with immediate effect :-

Sl. No.	Name of the Officer	Present Place of Posting	Posted as
1	Sh. Sudhir Kumar, IAS (AGMUT: 1999)	Principal Secretary (Vigilance)	Principal Secretary (Vigilance) with additional charge of Principal Secretary (AR)
2	Shri Nikhil Kumar, IAS (AGMUT:2002)	Secretary (Land & Building)	Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner with additional charge of Secretary (Land & Building)
3	Ms. Shilpa Shinde, IAS (AGMUT: 2006)	MD (DTC) & Additional Charge of Special Commissioner (Transport)	CEO (DJB)
4	Shri S. K. Jain, IAS (AGMUT: 2007)	Project Director (CATS) & additional charge of Special Secretary (H&FW)	Secretary (Art & Culture)
5	Shri Sachin Shinde, IAS (AGMUT:2008)	Addl. Commissioner (MCD)	MD (DTC) with additional charge of Special Commissioner (Transport) relieving Sh. Shahzad Alam, IAS (AGMUT: 2019) in compliance of MHA order dated 12.09.2024
6	Ms. Chanchal Yadav, IAS (AGMUT:2008)	Secretary (Home)	Commissioner (T&T) with additional charge of Secretary (WCD)
7	Ms. Arti Lal Sharma, IAS (AGMUT:2010)	DDA	Special Secretary (Planning)
8	Shri S. K. Singh, IAS (AGMUT: 2011)	Member (DUSIB)	Special Commissioner (T&T) with additional charge of Additional IG (Delhi Prison)
9	Shri Sanjeev Kumar Mittal, IAS (AGMUT: 2011)	MD (DSIIDC)	Special Commissioner (Road safety) in Transport Department.
10	Shri Ajay Kumar Bisht, IAS, (AGMUT: 2011)	Special Commissioner (T&T) and additional charge of Additional IG (Delhi Prison)	Staff Officer to Chief Secretary with additional Charge of Special Secretary (Vigilance)

Page 1 of 4

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर, दिसंबर तक चालू होगी राजधानी की तीसरी रिंग रोड; इन इलाकों के लोगों को होगा फायदा

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।हरियाणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार इसके अन्य हितधारक हैं। सड़क की कुल लंबाई 75.71 किमी में से 54.21 किमी दिल्ली में और 21.50 किमी हरियाणा में पड़ती है। यूईआर-II की परिकल्पना डीडीए द्वारा दिल्ली के लिए तीसरी रिंग रोड के रूप में की गई थी जिसने बाद में पांच पैकेजों के साथ बड़ा आकार ले लिया।

नई दिल्ली। बाहरी, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली में आवागमन को बेहतर बनाने के लिए 3,600 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही तीसरी रिंग रोड यानी शहरी विस्तार सड़क (यूईआर दो) दिसंबर तक चालू कर दी जाएगी।

बुधवार को एलजी वीके सक्सेना ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि शेष काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाना चाहिए।

एलजी ने मौजूदा बाधाओं और आगे की राह पर चर्चा की। मंगेशपुर नाले के ऊपर ओवरहेड रोड के चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी मिलने पर एलजी ने निर्देश दिया कि नाले के रास्ते में सड़क को सपोर्ट करने वाले किसी खंभे का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

नालों में खंभों के निर्माण से प्रवाह अवरुद्ध

बारापूला और कुशक नालों के साथ अपने हालिया अनुभव का हवाला देते हुए सक्सेना ने बताया कि इन नालों में खंभों के निर्माण ने उनके प्रवाह को काफी हद तक अवरुद्ध कर दिया था, जिससे भारी वर्षा के दौरान बाढ़ आ गई थी।

हरियाणा में है 21.50 किमी सड़क

गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) इस परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है।हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार इसके अन्य हितधारक हैं। सड़क

की कुल लंबाई 75.71 किमी में से 54.21 किमी दिल्ली में और 21.50 किमी हरियाणा में पड़ती है।

यूईआर-II की परिकल्पना डीडीए द्वारा दिल्ली के लिए तीसरी रिंग रोड के रूप में की गई थी, जिसने बाद में पांच पैकेजों के साथ बड़ा आकार ले लिया। पांच पैकेजों में से पैकेज एक, दो और तीन दिल्ली में हैं जबकि अन्य दो हरियाणा में हैं।

बाहरी रिंग रोड पर यातायात आसान हो जाएगा

डीडीए के मुताबिक, "इसके एक बार पूरी तरह से पूरा हो जाने पर, शहर में मौजूदा आंतरिक और बाहरी रिंग रोड पर यातायात आसान हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में सोनीपत और गुरुग्राम के बीच सीधी पहुंच प्रदान करने के साथ साथ बाहरी, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में भी आवागमन बेहतर होगा।"

गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ती है सड़क

यह परियोजना, जो दिल्ली में बवाना, नरेला-कंझावला, मुंडका और द्वारका आदि के बीच पूरे खंड के माध्यम से दक्षिणी दिल्ली में एनएच-44 (दिल्ली-चंडीगढ़ राजमार्ग) को एनएच-48 से जोड़ती है, उत्तर-पश्चिम में सोनीपत तक जाती है। इसमें एक मार्ग जींद, नजफगढ़ से बहादुरगढ़ तक जाने वाला है। यह हरियाणा के गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेसवे से भी जुड़ता है।

अधिकारियों के मुताबिक यह पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, जिसका उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा और यूपी में यातायात की भीड़, आसान पारगमन और प्रदूषण नियंत्रण का स्थायी समाधान प्रदान करना है।

डीडीए ने कहा कि एक बार पूरी तरह से चालू होने के बाद, इस परियोजना से दिल्ली के उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है।

दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, केजरीवाल सरकार में विवादों में रहे राजशेखर का भी हुआ ट्रांसफर; देखें लिस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एलजी सक्सेना ने कई आईएएस और दानिक्स अधिकारियों का तबादला किया है। विवादों में रहे राजशेखर को दिल्ली से बाहर भेजा गया है। निखिल कुमार को संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। शिल्पा शिंदे को दिल्ली जल बोर्ड में सीईओ बनाया गया है। शिक्षा विभाग में तीन महिला आईएएस अधिकारियों को तैनात किया गया है। रवि झा आबकारी विभाग में आयुक्त होंगे।

नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों के मामले में बड़ा फेरबदल किया, जिसमें कई आईएएस और दानिक्स अधिकारियों को अलग-अलग विभागों में स्थानांतरित किया गया, उनमें से कुछ को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गईं और कुछ को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दिल्ली से बाहर भेजा गया था। यह फेरबदल राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की सिफारिश और कुछ दिन पहले एलजी और सीएम आतिशी के बीच हुई चर्चा के बाद किया गया।

इस फेरबदल के तहत गृह मंत्रालय द्वारा विशेष सचिव (सतर्कता) वाइवीवीजे राजशेखर सहित तीन आईएएस अधिकारियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। एजीएमयूटी (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी राजशेखर सतर्कता विभाग में अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान अपने काम करने के तरीके के कारण चर्चा में रहे। इस दौरान कई विवाद भी हुए।

इस फेरबदल के तहत गृह मंत्रालय द्वारा विशेष सचिव (सतर्कता) वाइवीवीजे राजशेखर सहित तीन आईएएस अधिकारियों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। एजीएमयूटी (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 2012 बैच के आईएएस अधिकारी राजशेखर सतर्कता विभाग में अपने 2 .5 साल के कार्यकाल के दौरान अपने काम करने के तरीके के कारण चर्चा में रहे। इस दौरान कई विवाद भी हुए।

कथित कदाचार और भ्रष्टाचार के मामलों में कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच भी शुरू की। राजशेखर को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है। जबकि आयुक्त (श्रम) के रूप में कार्यरत आरएन शर्मा को जम्मू-कश्मीर भेजा गया है। वह शिक्षा निदेशक का प्रभार भी संभाल रहे थे। एलजी की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने 2002 बैच के आइएएस अधिकारी निखिल कुमार को संभागीय आयुक्त नियुक्त किया है। वह भूमि और भवन विभाग में सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे।

शिल्पा शिंदे को दिल्ली जल बोर्ड में CEO बनाया गया

शिल्पा शिंदे को डीटीसी से दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भेजा गया है। उनकी जगह 2008 बैच के आइएएस सचिन शिंदे को लाया गया है, जो एमसीडी में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। सचिन शिंदे परिवहन विभाग में विशेष आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे, जो शहजाद आलम की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले महीने एमएचए द्वारा लद्दाख स्थानांतरित किया गया था।

शिक्षा विभाग में तीन महिला आईएएस अधिकारी तैनात

एलजी ने शिक्षा विभाग में तीन महिला आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। 2015 बैच की अधिकारी वेदिता रेड्डी निदेशक के पद पर शामिल होंगी, जबकि 2016 बैच के अधिकारी नाजुक कुमार और 2020 बैच की श्रेया सिंघल को अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। इनके अलावा चंचल यादव को गृह विभाग के सचिव पद से मुक्त कर दिया गया है।वह आयुक्त (व्यापार एवं कर) का कार्यभार देखती रहेंगी। उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

आईएएस अधिकारी रवि झा आबकारी विभाग में आयुक्त

2011 बैच के अधिकारी रवि झा आबकारी विभाग में आयुक्त होंगे। वे नई दिल्ली जिले में डीएम के पद पर तैनात थे और लिंक अधिकारी के तौर पर आबकारी विभाग का प्रभार संभाल रहे थे। झा की जगह 2018 बैच के आइएएस अधिकारी सनी कुमार सिंह को नई दिल्ली का डीएम नियुक्त किया गया है।

विशेष सचिव (बिजली) रवि धवन को दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे संजीव कुमार मित्तल की जगह लेंगे, जिन्हें सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ में विशेष आयुक्त के पद पर परिवहन विभाग में स्थानांतरित किया गया है। धवन विशेष सचिव (बिजली) का प्रभार संभालते रहेंगे।

"सड़क सुरक्षा: #VocalForLocalRoadSafety स्थानीय पहल से बड़ा बदलाव"

गुरुग्राम और फरीदाबाद में सड़क दुर्घटनाएं आम हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है जब हम सभी मिलकर इसे रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। #VocalForLocalRoadSafety अभियान के माध्यम से रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन स्थानीय सड़क सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार की सहायता से यह फाउंडेशन बड़े पैमाने पर स्वयंसेवकों का नेटवर्क तैयार कर रही है, जो सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

इस अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य है कि हर नागरिक अपने स्थानीय क्षेत्र के सड़क सुरक्षा मुद्दों को पहचाने और उनकी रिपोर्टिंग करे। फरीदाबाद और गुरुग्राम के नागरिक अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों और पार्षदों के साथ मिलकर स्थानीय सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं।

इस अभियान में परिवहन विशेष की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सड़क सुरक्षा की दिशा में न केवल जागरूकता फैला रही है बल्कि नए सरकार के गठन के साथ इसे एक मुख्य एजेंडा के रूप में अपना रही है। यह पहल सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने, अवैध वाहनों पर नियंत्रण रखने और युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित है।

आज जब सड़क दुर्घटनाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं, तब सड़क सुरक्षा के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। #VocalForLocalRoadSafety अभियान से जुड़ें और सुनिश्चित करें कि हमारे शहर की सड़कों पर हम सभी सुरक्षित रहें।

roadsafetysquad@gmail.com

विशेष साक्षात्कार: परिवहन विशेष के साथ डॉ. अंकुर शरण

डॉ. अंकुर शरण, एक प्रतिष्ठित सामाजिक उद्यमी और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कई संस्थानों के साथ मिलकर काम किया है और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वर्तमान में, वे रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन के चीफ ट्रैफिक और प्लानिंग अधिकारी के रूप में #VocalForLocalRoadSafety अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस साक्षात्कार में, हम जानेंगे कि यह अभियान कैसे समाज को जागरूक करने और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने का काम कर रहा है।

परिवहन विशेषः नमस्कार, डॉ. शरण। आप सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और #VocalForLocalRoadSafety अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कृपया इस अभियान का उद्देश्य और इसका महत्व बताएं।

डॉ. अंकुर शरणः नमस्कार। #VocalForLocalRoadSafety का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। हमारा मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल ट्रैफिक नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामुदायिक जिम्मेदारी है। इस अभियान के माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ रहे हैं ताकि हर कोई अपने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी निभा सके।

हमने देखा है कि छोटी-छोटी अनदेखी, जैसे हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, या ओवरस्पीडिंग, बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं। इसलिए, हम विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और ड्राइव्स के माध्यम से लोगों को इन बुनियादी सुरक्षा उपायों की अनिवार्यता के बारे में शिक्षित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि सड़कें न केवल सुरक्षित हों, बल्कि हर व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका समझे और उसे निभाए।

परिवहन विशेषः डॉ. अंकुर शरण, Road Safety Squad की आवश्यकता क्यों पड़ी, और आपने विभिन्न क्षेत्रों से इतने सारे स्वयंसेवकों को कैसे जोड़ा?

डॉ. अंकुर शरणः रोड सेफ्टी स्क्वॉड की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही थी, जिससे न केवल लोगों की जान जा रही थी बल्कि परिवारों पर भी गहरा असर पड़ रहा था। हमें एहसास हुआ कि केवल सरकारी प्रयासों से ही सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, जब तक कि समाज का हर वर्ग इसमें सक्रिय भागीदारी न निभाए।

हमने स्वयंसेवकों को जोड़ने के लिए #VocalForLocalRoadSafety अभियान शुरू किया, जिसमें हम लोगों को उनकी स्थानीय सड़कों और उनके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमने छात्रों, पेशेवरों, गृहिणियों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया, ताकि हर कोई अपने-अपने तरीके से योगदान दे सके। हमारा उद्देश्य था कि सड़क सुरक्षा को एक जनांदोलन बनाया जाए, जहां हर व्यक्ति इस मिशन का हिस्सा बने।

परिवहन विशेषः आपने विभिन्न अभियानों का आयोजन किया है, जैसे हेलमेट जागरूकता ड्राइव और स्कूली छात्रों के लिए जागरूकता अभियान। भविष्य में और कौन-कौन से अभियान शुरू करने की योजना है?

डॉ. शरणः हम कई नए अभियानों की योजना बना रहे हैं। जैसे कि 'ओवरस्पीडिंग रोकथाम अभियान,' जिसमें लोगों को ओवरस्पीडिंग के खतरों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा, 'सीट बेल्ट अनिवार्यता अभियान' शुरू करने की भी योजना है, जिसमें हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न केवल ड्राइवर बल्कि पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो। हमारा उद्देश्य है कि हर कोई सुरक्षित यात्रा करे।

परिवहन विशेषः आपने बताया कि आप बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं, यह कैसे संभव हो पाएगा?

डॉ. शरणः बच्चों को शामिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि वे हमारे भविष्य के चालक और पैदल यात्री हैं। 'रास्ता सुरक्षा बाल मित्र अभियान' के माध्यम से हम बच्चों को सड़क सुरक्षा के मूलभूत नियम सिखाएंगे। इसके तहत हम स्कूली बच्चों के लिए रोचक गतिविधियां और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करेंगे ताकि वे आसानी से सीख सकें और अपने परिवार एवं दोस्तों को भी जागरूक कर सकें।

परिवहन विशेषः इस अभियान को सफल बनाने के लिए समाज से किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है?

डॉ. शरणः समाज की भागीदारी के बिना इस अभियान को सफल बनाना मुश्किल है। हमें चाहिए कि लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, ओवरस्पीडिंग न करें, और हेलमेट तथा सीट बेल्ट का उपयोग करें। इसके अलावा, हमें यह भी चाहिए कि लोग सड़क पर किसी भी खतरनाक स्थिति को देखकर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

परिवहन विशेषः आपके विचार में हरियाणा सरकार और संबंधित अधिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए?

डॉ. शरणः सरकार और संबंधित अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नए ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करना, सड़क संकेतकों की नियमित निगरानी, और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी है। साथ ही, हमें सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा देना होगा ताकि सड़क सुरक्षा केवल एक सरकारी पहल न रहे, बल्कि यह एक जनांदोलन बन जाए।

परिवहन विशेषः डॉ. अंकुर शरण, आप एक लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पेशेवर हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि सड़क सुरक्षा इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है?

डॉ. अंकुर शरणः सड़क सुरक्षा लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर ट्रांसपोर्टेशन की विश्वसनीयता, समयबद्धता, और लागत को प्रभावित करती है। यदि सड़कें सुरक्षित नहीं हैं, तो न केवल माल की डिलीवरी में देरी होती है, बल्कि हादसों की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे नुकसान और परिचालन लागत में वृद्धि होती है।

सड़क दुर्घटनाओं के कारण ट्रकों और अन्य वाहनों का नुकसान होता है, जिसके परिणामस्वरूप सप्लाई चेन में रुकावटें आती हैं। साथ ही, जब ड्राइवर सुरक्षित नहीं हैं या सड़क पर जोखिम का सामना करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव उनकी कार्यक्षमता और मनोबल पर पड़ता है।

हमारे लिए आवश्यक है कि हम सड़क सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दें, जैसे कि ड्राइवरों की नियमित ट्रेनिंग, वाहनों की समय पर जांच, और रूट प्लानिंग में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए। इससे न केवल आपूर्ति श्रृंखला की सुचारूता बनी रहेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा।

परिवहन विशेषः आपका जवाब बहुत ही प्रेरणादायक है। धन्यवाद, डॉ. शरण, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए।

डॉ. अंकुर शरणः धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर सड़क सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बेहतर बदलाव ला सकेंगे।

2026 के बाद नहीं दौड़ेंगे डीजल ऑटो रिक्शा, ओवरएज वाहनों को हटाने की तैयारी; NCR में बसों के लिए बना नया प्लान

पर्यावरण से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में मौजूदा समय में करीब 1.50 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड है जो हर साल करीब छह प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ रहे है जबकि इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या सिर्फ 3 लाख ही है। कुल रजिस्टर्ड वाहनों में करीब 90 लाख दोपहिया वाहन है। गौरतलब है कि एनसीआर में मौजूदा समय में दिल्ली के अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों के करीब 26 जिले शामिल है।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में हर साल अक्टूबर-नवंबर महीने में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के पीछे भले ही पराली एक बड़ी वजह है लेकिन इन हवाओं को जानलेवा बनाने में वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं दूसरी बड़ी वजह है।

डीजल वाले ऑटो रिक्शा से मुक्ति

बढ़े प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक होती है। जो पीएम (पार्टीकुलेट मैटर) -10 के स्तर को कम लेकिन पीएम (पार्टीकुलेट मैटर)-2.5 के स्तर को ज्यादा प्रभावित करती है। यही वजह है कि इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई सख्त कदम उठाए है। जिसमें 2026 तक एनसीआर के सभी जिलों को डीजल से दौड़ने वाले ऑटो रिक्शा से मुक्ति दिलाई जाएगी।

बसों को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने की योजना

इसके पहले चरण में इसी साल दिसंबर तक नोयडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद को डीजल ऑटो रिक्शा से मुक्ति मिल जाएगी। दिल्ली में हर दिन दूसरे राज्यों से आने वाले बसों को बीएस-6 या फिर सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों में शिफ्ट करने की योजना है।

ओवरएज वाहनों को हटाने की तैयारी

मौजूदा समय में दिल्ली आने वाली इन बसों की संख्या 17 सौ से अधिक है। इस साल दिसंबर तक इस बसों को बीएस-6 या सीएनजी, इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त ओवरएज हो चुके वाहनों को भी सड़कों से हटाने की तैयारी है।

कहां-कितने ओवरएज वाहन?

अकेले दिल्ली में मौजूदा समय में 59 लाख से अधिक ओवरएज वाहन है, वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 12 लाख, हरियाणा में करीब 27 लाख, राजस्थान में करीब छह लाख है। हालांकि, सख्ती न होने के चलते यह सभी वाहनों अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे है।

दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से होने वाला प्रदूषण एक नजर में

वायु प्रदूषण में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी- 30 प्रतिशत से अधिक

पीएम- 2.5 में हिस्सेदारी- करीब 40 प्रतिशत

पीएम-10 में हिस्सेदारी- 20 प्रतिशत

दिल्ली में कुल वाहन की संख्या- 1.50 करोड़

इनमें आयु पूरी कर चुके वाहनों की संख्या- 59 लाख

ई-वाहनों की संख्या- करीब तीन लाख।

हर दिन दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की संख्या- करीब एक लाख।

अगले साल तक दिल्ली में होंगे 18 हजार चार्जिंग प्वाइंट

वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए मौजूदा समय में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रमोट करने में केंद्र व राज्य सरकारें जुटी हैं। इसके तहत इन वाहनों की खरीदी में सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली में वर्ष 2025-26 तक 18 हजार चार्जिंग प्वाइंट बनाने की भी योजना बनाई गई है। यह बात अलग है कि पहले जो भी चार्जिंग स्टेशन और प्वाइंट बनाए गए थे, उनमें से ज्यादातर बंद या खराब पड़े है।

करोड़ों वाहन चालकों के लिए बुरी खबर! पांच रुपये प्रति किलो महंगी हो सकती है CNG, पढ़ें क्या है वजह

सीएनजी वाहन चालकों को दीवाली से पहले झटका लगा सकता है। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। सीएनजी पांच रुपये प्रति किलो महंगी हो सकती है। दरअसल शहरी गैस कंपनियों को देश में उत्पादित होने वाली सस्ती गैस की आपूर्ति में 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। ऐसे में कंपनियों को अपना फायदा बरकरार रखने में सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है।

नईदिल्ली। सरकार ने सीएनजी की खुदरा बिक्री करने वाली शहरी गैस कंपनियों को देश में उत्पादित होने वाली सस्ती गैस की आपूर्ति में 20 प्रतिशत तक की कटौती की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कंपनियों को अपना लाभ बरकरार रखना है तो उन्हें पांच से साढ़े पांच रुपये प्रति किलो सीएनजी का मूल्य बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा होने पर सीएनजी वाहनों की बिक्री धीमी हो सकती है।

विधानसभा चुनावों के बाद बढ़ोतरी संभव

हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि सीएनजी कीमतों में बढ़ोतरी को महाराष्ट्र एवं झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनावों तक टाला जा सकता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) और महानगर गैस लिमिटेड ने शेयर बाजारों को बताया कि घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की आपूर्ति में कटौती की गई है। इस गैस का मूल्य आयातित गैस की कीमत से लगभग आधा है।

शेयर बाजार को दी सूचना में क्या बोला IGL

बता दें आईजीएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य (6.5 डॉलर प्रति एमबीटीयू) पर सीएनजी बिक्री मात्रा की जरूरत पूरी करने के लिए घरेलू गैस मिलती है, लेकिन नोडल एजेंसी गेल इंडिया से मिली जानकारी के मुताबिक 16 अक्टूबर से कंपनी को घरेलू गैस आवंटन में बड़ी कमी आई है।

सीएनजी के दाम में क्यों हो सकता है इजाफा?

आईजीएल ने कहा कि उसका संशोधित घरेलू गैस आवंटन पिछले आवंटन से लगभग 21 प्रतिशत कम है, जिसका असर उसके लाभ पर पड़ेगा। महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने कहा कि सीएनजी के लिए उसका आवंटन पिछले औसत तिमाही आवंटन की तुलना में 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए कंपनी नए विकल्पों पर विचार कर रही है।

बिहार में सीएनजी के दाम में कमी

हाल ही में बिहारवासियों को सौगात मिली थी। राज्य सरकार ने पीएनजी-सीएनजी पर वैट की दर में भारी कमी की घोषणा की। राज्य सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि प्राकृतिक गैस पर अभी तक 20 प्रतिशत की दर से वैट की वसूली हो रही थी। अब यह दर 12.5 से पांच प्रतिशत के बीच होगी। वहीं, घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग हेतु पीएनजी पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत किया गया है। मोटर वाहनों के लिए सीएनजी की दर भी अब 20 प्रतिशत के बजाय 12.5 प्रतिशत होगी।

असम में ट्रेन हादसा, डिबालोंग में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे

असम के डिबालोंग स्टेशन के पास एक ट्रेन डिरेल हो गई है। डिबालोंग में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि ट्रेन डिरेल की वजह से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह दुर्घटना लुमडिंग डिवीजन के लुमडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन में हुई। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लुमडिंग से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है।

नईदिल्ली। असम के डिबालोंग स्टेशन के पास एक ट्रेन डिरेल हो गई है। डिबालोंग में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि ट्रेन डिरेल की वजह से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह दुर्घटना लुमडिंग डिवीजन के लुमडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन में हुई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी इस दुर्घटना की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल हैंडल एक्स पर दी।

दुर्घटना दोपहर करीब 3:55 बजे हुई

रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि आज सुबह अगरतला से रवाना हुई मुंबई जाने वाली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस असम के डिबालोंग स्टेशन पर दोपहर करीब 3:55 बजे पटरी से उतर गई।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन के सीपीआरओ ने बताया, 'ट्रेन के पावर कार और इंजन समेत आठ डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है।'

इंजन सहित 8 डिब्बे पटरी से उतर

सीपीआरओ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कहा कि अगरतला से आज सुबह रवाना हुई 2520 अगरतला-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस लुमडिंग डिवीजन के अंतर्गत डिबालोंग स्टेशन पर लुमडिंग-बदरपुर हिल सेक्शन में लगभग 15-55 बजे पटरी से उतर गई। ट्रेन के पावर कार और इंजन सहित 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।

बचाव और बहाली कार्यों की निगरानी

दुर्घटना राहत ट्रेन और दुर्घटना राहत चिकित्सा ट्रेन बचाव और बहाली कार्यों की निगरानी के लिए डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लुमडिंग से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। लुमडिंग-बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है।

घटना स्थल पहुंची राहत टीम

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना राहत ट्रेन और दुर्घटना राहत चिकित्सा ट्रेन बचाव और बहाली कार्यों की निगरानी के लिए डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लुमडिंग से घटनास्थल पर पहुंच चुकी है।

हेल्पलाइन नंबर जारी

सीपीआरओ ने बताया कि लुमडिंग-बदरपुर सिंगल लाइन सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 03674 263120, 03674 263126 जारी कर दिया गया है।

रविवार को तड़के सवा तीन बजे से शुरू होगा मेट्रो का परिचालन, DMRC ने दिया अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

रविवार को होने वाली दिल्ली हाफ मैराथन के कारण दिल्ली मेट्रो का परिचालन तड़के 315 बजे से शुरू होगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन और ग्रे लाइन को छोड़कर अन्य सभी कॉरिडोर पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी। धावकों के लिए विशेष क्यूआर कोड वाले कलाई बैंड होंगे और वे निशुल्क मेट्रो में सफर कर सकेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी हाफ मैराथन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाफ मैराथन के कारण रविवार को तड़के सवा तीन बजे से मेट्रो का परिचालन होगा। इस वजह से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (नई दिल्ली-टर्मिनल तीन) और ग्रे लाइन (द्वारका-ढांसा बस स्टैंड) को छोड़कर अन्य सभी मेट्रो कॉरिडोर पर तड़के सवा तीन बजे से मेट्रो उपलब्ध होगी।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अनुसार हाफ मैराथन में भाग लेने वाले धावकों के मेट्रो में सफर का किराया आयोजक भरेंगे। उनकी जरूरत के अनुसार डीएमआरसी क्यूआर कोड टिकट उपलब्ध कराएगा। धावक निःशुल्क मेट्रो में सफर कर सकेंगे।

15-20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन

हाफ मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावक आयोजकों से विशेष क्यूआर कोड वाले कलाई बैंड ले सकते हैं। तड़के सवा तीन से चार बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन होगा। सुबह चार से छह बजे के बीच 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। सुबह छह बजे से सभी कॉरिडोर पर अपने निर्धारित समय से मेट्रो उपलब्ध होंगी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी हाफ मैराथन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। हाफ मैराथन के मद्देनजर रविवार को सुबह 11 बजे तक दक्षिण और मध्य दिल्ली में यातायात प्रभावित रहेगा। एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली हाफ मैराथन में 35,000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसे सुबह 4.45 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।

हाफ मैराथन की टाइमिंग

हाफ मैराथन ओपन और पुलिस कप 21.09 किलोमीटर सुबह 5 बजे जेएलएन स्टेडियम से शुरू होगा। एलीट एथलीट पुरुष और महिला (भारतीय और अंतरराष्ट्रीय) हाफ मैराथन 21.09 किलोमीटर सुबह 6.50 बजे जेएलएन स्टेडियम परिसर से शुरू होगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि ओपन हाफ मैराथन (10 किमी) सुबह 7.30 बजे संसद मार्ग पर जीवन दीप बिल्डिंग से शुरू होगी।

एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्रियों से अनुरोध है कि वे फिटनेस के इस उत्सव में सहयोग करें और दिल्ली हाफ मैराथन के आसपास की सड़कों और जंक्शनों से बचें तथा ऊपर बताए गए सुझाए गए मार्गों से यात्रा करें।

संसदीय क्षेत्रों में दिल्लीवालों आओ, दिल्ली चलाओ अभियान के तहत जनता की सलाह लेने के लिए सात वेन रवाना

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने विधानसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बजाते हुए आज भारी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी में दिल्लीवालों आओ, दिल्ली चलाओ अभियान के साथ सभी सात संसदीय क्षेत्रों में सात वेन हरी झंडी दिखाकर रवाना की। प्रत्येक वेन में एक खाली कुर्सी रखी गई है जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली की जनता को बैठाकर उनसे दिल्ली कैसे चलानी है और दिल्ली में कांग्रेस क्या बेहतर कर सकती है, यह पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले दिल्ली की जनता से उनके विचार, सलाह लेकर कांग्रेस घोषणा पत्र न्याय संकल्प में सम्मिलित करेगी।

ज्ञातव्य है कि कांग्रेस पार्टी ने कनॉट प्लेस में मेनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की, जिसमें जनता के बीच एक खाली कुर्सी रखकर घोषणा की थी कि जिस प्रकार दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने बराबर में अरविन्द केजरीवाल के लिए एक खाली कुर्सी रखकर दिल्ली की सरकार चला रही है। दिल्ली कांग्रेस उसी तर्ज पर दिल्ली की जनता को खाली कुर्सी पर बैठाकर उनके विचार लेगी कि बदहाल हो चुकी दिल्ली की बेहतरी कैसे होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री को कुर्सी पर जनता बैठाती है, इसलिए हमने दिल्ली की जनता के लिए सभी संसदीय क्षेत्रों में जनता के विचार लेने के लिए खाली कुर्सी रखकर वेन भेजी है। दिल्लीवालों के भी कुछ सपने है, भविष्य की सोच है। वेनों पर दिल्लीवालों आओ, दिल्ली चलाओ और हाथ बदलेगा हालात जैसे नारे लिखे हुए है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कुशासन और भाजपा की तानाशाही को कैसे खत्म कर सकते है, अब सब कुछ दिल्ली की जनता बताऐगी। उन्होंने कहा कि इनके मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में रहे, विधायकों का जेल आना जाना लगा रहता है। अगर देखें तो दिल्ली सरकार की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली पूरी तरह रुक गई है।

यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित जिला अध्यक्ष, ब्लाक अध्यक्ष, पूर्व विधायक, निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद, विधानसभा वे निगम प्रत्याशियों से अपील की कि हाथ बदलेगा हालात की मुहिम में दिल्लीवालो आओ दिल्ली चलाओ वेन में जनता की खाली कुर्सी पर जनता के बीच जाकर अधिक से अधिक लोगों से बातचीत करके दिल्ली कैसे चलानी है, हर विषय पर चर्चा करनी है, उनके सुझाव लेने है। दिल्ली की जनता से महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल दिल्ली, ढांचागत व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, परिवहन, टूटी सड़कें, कानून व्यवस्था, सामाजिक कल्याण, महिला सुरक्षा, बच्चों में फैलता कुपोषण, हर वर्ष मानसून के दौरान जल भराव के कारण मरते लोग, भरी हुई नाली और नाले और हर वर्ष डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से मरते लोग क्यों मर रहे है। कांग्रेस कार्यकर्ता बाजारों, कालोनियों के चौक, रिहायशी क्षेत्रों की गलियों में दुकानदारों, रेहड़ी पटरीवालों, ऑटो टैक्सी, मजदूरों, कामगार, युवाओं, महिलाओं, किसानों, आरडब्लूए हर विषय पर जनता से सलाह और सुझाव मांगे।

सभी सात संसदीय क्षेत्रों में प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव और अ0भा0क0कमेटी के सचिव सुखविंदर सिंह डैनी ने सभी वेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पूर्व सांसद रमेश कुमार, अ0भा0क0कमेटी के सचिव अभिषेक दत्त, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारुन यूसूफ और डा0 नरेन्द्र नाथ, पूर्व विधायक एवं कम्युनिकेशनt विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक हसन अहमद, भीष्म शर्मा, कुंवर करण सिंह, हरी शंकर गुप्ता, आसिफ मौहम्मद खान, विजय लोचव, अमरीश गौतम और सुरेन्द्र कुमार, अ0भा0क0कमेटी प्रवक्ता आलोक शर्मा, मेनिफेस्टों कमेटी के कन्वीनर चतर सिंह, निगम पार्षद हाजी जरीफ, जिला अध्यक्ष मदन खोरवाल, मनोज यादव, धर्मपाल चंदेला, गुरचरण सिंह राजू, इन्द्रजीत सिंह, जुबैर अहमद, विरेन्द्र कसाना, विष्णु अग्रवाल, दिनेश कुमार, जावेद मिर्जा, सतबीर शर्मा, प्रदेश महिला अध्यक्ष पुष्पा सिंह, सेवादल मुख्य संगठक सुनील कुमार सहित सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

सदर बाजार में अवैध पटरी व अतिक्रमण रोकने के लिए पुलिस की तनाती ज्यादा हो - पम्मा व राकेश यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। सदर बाजार में जाम हुआ अवैध पटरी को लेकर व महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजी करते हुए वीडियो वायरल हुए थे। इसको लेकर व्यापारियों में काफी गुस्सा था। जिसे फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन ने प्रशासन को चेतावनी दी थी अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो वह सड़कों पर उतरेंगे।

फेडरेशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश यादव महासचिव राजेंद्र शर्मा व कोषाध्यक्ष दीपक मित्तल बताया कि हमारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस व मेट्रो के सभी अधिकारियों के साथ त्योहार से पहले एक बैठक की थी जिसमें हमने उनको बताया था कि त्योहारों पर सदर बाजार में रश हो सकता है। जिसके लिए वह अधिक स्टाफ लगा कर

रखें। मगर कुछ कमियां होने के कारण इस प्रकार दिक्कत आई है। मगर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने आज सदर बाजार में डीसीपी नॉर्थ एसीपी सदर बाजार, एस एच ओ सदर बाजार की अध्यक्षता में दौरा किया जिसमें अवैध पटरी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की

परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव मांग की इसी प्रकार के मार्केट में लगातार ग्रस्त होनी चाहिए जिसमें अवैध पटरी, अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कार्रवाई की जाए।

परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने बताया सदर बाजार थाने की ओर से एक रोड मैप जारी किया गया जिसमें उन्होंने मार्केट में ई-रिक्शा को रोकने के लिए कई जगह बैरिकेड लगाए जाएंगे जिसमें मार्केट में रश हो और लोग खरीददारी बड़े आराम से कर सके।

सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड को शिव शक्ति रामलीला में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए किया सम्मानित

परिवहन विशेष न्यूज

दक्षिणी दिल्ली: सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड द्वारा शिव शक्ति रामलीला एवं मेला में 03 अक्टूबर से 17 अक्तूबर 2024 तक अपनी निष्काम सेवा देने के लिये रामलीला एवं मेला प्रधान श्री ओ पी अरोड़ा जी ने सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड के दक्षिण दक्षिणी पुर्वी दिल्ली के असिस्टेंट कमिशनर श्री पी ड़ी वर्खिया को उनकी व उनकी टीम की उत्कृष्ट सेवाओं के लिये प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।

01 श्री दिलीप कुमार डिवीजन कमांडर।

02 कुमारी प्रीति वर्खिया सार्जेंट नर्सिंग।

03 श्रीमती सज्जन सार्जेंट नर्सिंग।

04 श्रीमती माधुरी सार्जेंट नर्सिंग।

सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड निष्काम सेवा करती है। फ़र्स्टएड पोस्ट लगवाने के लिये आप दिल्ली ब्रिगेड को रिक्वेस्ट लैटर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं।

अतिरिक्त आयुक्त/additional Commissinor St. John Ambulance Brigade Delhi

stjohnambulancedelhi@yahoo.com

हमने श्री वर्खिया जी से पूंछा की संस्था की सदस्यता कैसे मिल सकती है कौन सदस्य बन सकता है। उन्होंने बताया कि संस्था की सदस्यता देश का कोई भी नागरिक महिला पुरुष सदस्यता ले सकते हैं। केवल आपके पास आधार कार्ड और फ़र्स्टएड का सर्टिफिकेट होना चाहिये।

सेन्ट जोहन एम्बुलेंस ब्रिगेड यूनिफार्म बॉडी है। तो आपको अपनी यूनिफॉर्म भी स्वयं तैयार करनी होगी। पुरुषों के लिये खाकी पेंट शर्ट व महिलाओं के लिये सफेद सूट सलवार या सफेद साड़ी अधिक जानकारी हेतु पी डी वर्खिया असिस्टेंट कमिशनर मो0 9810982008 पर बात कर सकते हैं।

अब अरविंद केजरीवाल वापस आ गए हैं तो दिल्ली में काम होना शुरू हो गए हैं : सौरभ भारद्वाज

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के जन संपर्क अभियान के तहत आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र ग्रेटर कैलाश विधानसभा के जगदंबा कैंप से इस अभियान की शुरुआत की। सौरभ भारद्वाज ने घर-घर जाकर लोगों को अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली की जनता के नाम लिखी चिट्ठी बांटी और साथ ही साथ लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाया, कि आखिर अरविंद केजरीवाल को इतने महीनो तक जेल में रखने के पीछे का सच क्या है। सौरभ भारद्वाज ने लोगों को बताया कि कैसे एक षड्यंत्र करके झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को फंसा कर इतने महीनो तक जेल में बंद रखा गया और उनको जेल में बंद रखने के पीछे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का असली मकसद क्या था। भाजपा शासित 22 राज्यों में रहने वाले लोग भाजपा से दिल्ली जैसी सुविधाओं की मांग करते हैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली के गवर्निंग मॉडल को बर्बाद करना चाहती है, ताकि अन्य भाजपा शासित राज्यों के लोगों को जवाब ना देना पड़े।

यह अभियान आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा के चिराग दिल्ली वार्ड में स्थित जगदंबा कैंप से शुरू किया गया। आम आदमी पार्टी के इस जनसंपर्क अभियान को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। लोग अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं और उनके द्वारा कही गई बातें लोगों को भली-भांति समझ में आ रही है और लोग भारतीय जनता पार्टी के असली मकसद को अब पहचान गए हैं। अब यह डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रहेगा और इस अभियान के तहत पूरी विधानसभा में हर एक क्षेत्र में घर-घर जाकर अरविंद केजरीवाल की यह चिट्ठी जनता को पहुंचाई जाएगी और साथ ही साथ लोगों से बातचीत कर उनको अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की असली मंशा का खुलासा किया जाएगा।

जनसंपर्क अभियान के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जनता सभी बातों को भली-भांति जानती है और यह अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी जो हम लोगों के बीच घर-घर जाकर बांट रहे हैं, इसमें अरविंद केजरीवाल ने उस बात का जवाब दिया है, जो प्रश्न जनता के मन में अभी तक था, कि एक झूठे मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को इतने महीनो तक क्यों बंद रखा गया? क्यों उनको दी जाने वाली इंसुलिन बंद की गई? क्यों उन्हें मारने की कोशिश की गई?

उन्होंने कहा कि चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने बताया है, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद पीछे से दिल्ली के पूरे सिस्टम को ठप करने की कोशिश की गई। अस्पतालों की दवाइयां को रोका गया, मोहल्ला क्लिनिको में होने वाले मुफ्त टेस्ट को रोका गया, बुजुर्गों की पेंशन चार महीने तक रोकी गई, डॉक्टरों का वेतन रोका गया, पानी, सीवर के और सड़कों के निर्माण के कार्य रोके गए। परंतु अब जब केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, तो यह सभी काम दोबारा से शुरू हो गए हैं। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को इन सभी कामों से अब तकलीफ हो रही है। इसलिए अब उनकी कोशिश है, कि किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता को हथिया कर दिल्ली का वह मॉडल जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे दिल्ली और देश के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल ने बनाया है, उसे ठप किया जाए। उन्होंने कहा की यही सब बातें हम केजरीवाल की इस चिट्ठी के माध्यम से घर-घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं और लोग इस बात को भली भांति समझ भी रहे हैं।

दिल्ली के प्रदूषण पर भाजपा-आप फिर आईं आमने-सामने, एक दूसरे पर फोड़ा ठीकरा

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के पीछे असली कारण भाजपा शासित पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारें प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं। हरियाणा और यूपी में प्रदूषण कम करने को लेकर गंभीर नहीं है।

नई दिल्ली। दूसरे राज्यों के प्रदूषण पर आप और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण के पीछे असली कारण भाजपा शासित पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं।

आप के वरिष्ठ नेता जस्मिन शाह ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की एजेंसी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जारी आंकड़ों से साफ हुआ है कि पूरे भारत में केवल आप की दिल्ली-पंजाब की सरकारें ही प्रदूषण कम करके जनता को राहत दिला रही हैं, बाकी सभी राज्य सरकारें सो रही हैं।

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 27 फीसदी की कमी आई

खासकर दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारें प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं। उन्होंने आंकड़े रखते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले एक से 14 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 27 फीसदी की कमी आई है, जबकि हरियाणा में 23 और उत्तर प्रदेश में 71 फीसदी की वृद्धि हुई है।

भाजपा शासित सरकारें प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं

आप का कहना है कि भाजपा शासित सरकारें हरियाणा और यूपी में प्रदूषण कम करने को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए उसने धूल प्रदूषण को कम करने के लिए भी दिल्ली की तरह कोई विंटर एक्शन प्लान नहीं बनाया है।

पंजाब में सत्ता आने के बाद पराली पर केजरीवाल ने आंखें मूंदी

भाजपा दिल्ली भाजपा प्रवक्ता एवं डीपीसीसी सदस्य डा. अनिल गुप्ता और अधिवक्ता न्योमा गुप्ता ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब सरकार के प्रवक्ताओं की तरह बयान दे रहे हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की विफलता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिल्ली और उत्तर भारत में सर्दियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली जलाने पर रोक लगाने में असमर्थ रही है।

केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को गुमराह करने की कोशिश की

भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि आप प्रवक्ता जस्मिन शाह ने एक अज्ञात रिपोर्ट का हवाला देकर दिल्लीवासियों को गुमराह करने की कोशिश की है। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि शाह और अन्य आप नेताओं को समझना चाहिए कि यह एक स्थापित भौगोलिक तथ्य है कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आने वाली हवाएं दिल्ली में प्रदूषण लाती हैं।

नई सरकार का नया काम: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर जाम से मिलेगी मुक्ति, मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

राव नरबीर ने मंत्री बनते ही शहर के विकास के लिए प्लान तैयार कर लिया है। राव नरबीर सिंह ने दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे को जाम से मुक्ति दिलाना है। राव नरबीर जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

गुरुग्राम। प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने राव नरबीर सिंह की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे को जाम से मुक्ति दिलाना है। वह अगले एक सप्ताह के भीतर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे।

राव उनसे एक्सप्रेस-वे को एलिवेटेड कराने की मांग ही नहीं करेंगे बल्कि तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर काम शुरू कराने का आग्रह करेंगे। उनका मानना है कि एक्सप्रेस-वे पर जाम से गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली का भी विकास प्रभावित हो रहा है।

वहीं, इसका असर दिल्ली एवं हरियाणा के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के ऊपर पड़ रहा है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कई राज्यों को जोड़ने की लाइफ लाइन है।

बृहस्पतिवार को पंचकूला से फोन पर दैनिक जागरण से बातचीत में राव नरबीर सिंह ने कहा कि यदि वह वर्ष 2019 से 2024 तक सरकार में मंत्री रहते तो आज गुरुग्राम की हालत दयनीय नहीं होती। सरकार में स्थानीय प्रतिनिधित्व का मजबूत होना आवश्यक होता है।

इस बार उन्हें जनता ने मौका दिया है। अगला पांच साल गुरुग्राम के लिए स्वर्णिम काल होगा। इतने विकास कार्य कराए जाएंगे जितने पिछले कई सालों में नहीं हुए होंगे। गुरुग्राम की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। तस्वीर बदलने के लिए सबसे पहले दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे को जाम से मुक्ति दिलाना है। यह मुक्ति तभी मिलेगी जब एक्सप्रेस-वे को एलिवेटेड किया जाएगा। आज गुरुग्राम से दिल्ली जाना मुश्किल है। कब कितना समय लग जाएगा, यह पता नहीं। पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है।

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी एक्सप्रेस-वे की परेशानी से अवगत हैं। इससे उम्मीद है कि जल्द ही एलिवेटेड कराने की योजना पर काम शुरू होगा। इसके बाद उनका प्रयास होगा जितनी जल्द हो जिला नागरिक अस्पताल का शिलान्यास कराना।

निर्धारित समय के भीतर अस्पताल का निर्माण पूरा कराया जाएगा। यही नहीं जिले में कम से कम चार नागरिक अस्पताल हो, इस दिशा में भी उनका प्रयास होगा। अन्य समस्याओं में साफ-सफाई बहुत बड़ी नहीं है। केवल इसके ऊपर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव जीतने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि शहर में गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसके ऊपर काम शुरू भी हो गया है। जल्द ही शहर साफ-सुथरा दिखाई देगा।

शहर की अधिकतर सड़कों को एलिवेटेड कराने को लेकर जल्द ही प्लॉनिंग की जाएगी ताकि आंतरिक सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव न दिखे। इसके लिए पुराने गुरुग्राम ही नहीं बल्कि मानेसर एवं सोहना तक के इलाके में मेट्रो विस्तार के ऊपर जोर दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास कार्य होंगे। अगले पांच साल के भीतर 10 से अधिक फ्लाईओवर एवं अंडरपास बनवाए जाएंगे।

औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाएं विकसित करने के ऊपर जोर दिया जाएगा। नाम के अनुरूप गुरुग्राम दिखाई दे, इसे ध्यान में रखकर काम कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। प्रदूषण न फैले इसके लिए वह जल्द संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

24 घंटे खुले रहेंगे दरवाजे

राव नरबीर सिंह का कहना है कि लोगों की समस्याओं के लिए उनके दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अधिकारियों के दरवाजे न खटखटाने पड़े। बादशाहपुर इलाके में खरखौदा की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराने की दिशा में जल्द ही प्रयास शुरू किया जाएगा।

इसके लिए वह उद्यमियों के साथ संवाद करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से जहां गुरुग्राम का विकास तेजी से होगा वहीं लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होंगे।

ED ने गाजियाबाद के बिल्डर राजीव त्यागी को किया गिरफ्तार, 22 करोड़ की ठगी मामले में की थी पूछताछ

गाजियाबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनियन बैंक से 22.20 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में गाजियाबाद के बिल्डर राजीव त्यागी को गिरफ्तार किया है। आरोपित बिल्डर को पूछताछ के लिए लखनऊ स्थित जोनल कार्यालय बुलाया गया था। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। ईडी ने साक्ष्यों के आधार पर बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया।

ईडी ने 23 सितंबर को बिल्डर राजीव त्यागी व उसके बेटों की 14.89 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं। इनमें औद्योगिक व रिहायशी भूखंड, दुकान, कार्यालय व फ्लैट शामिल हैं। साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के निदेशक राजीव त्यागी के बेटे अर्मत्य राज त्यागी व कनिष्क राज त्यागी भी अलग-अलग फर्मों के संचालक हैं। इनमें एसकेटी गारमेंट्स लिमिटेड व एसके इंटरप्राइजेज शामिल हैं।

लोन के लिए गिरवी संपत्तियों के दस्तावेजों का किया प्रयोग

गाजियाबाद के साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स व उसकी सहयोगी फर्मों द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 22.20 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था, जिसे चुकाया नहीं गया। ईडी की जांच में सामने आया कि राजीव त्यागी अपनी पत्नी मीनू त्यागी के नाम से साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स का संचालन कर रहे थे। मीनू कंपनी में साझेदार थीं। आरोपितों ने यूनियन बैंक से करोड़ों रुपये का ऋण हासिल करने के लिए अपनी पहले से ही यूको बैंक में गिरवी संपत्तियों के दस्तावेजों का प्रयोग किया था।

यूनियन बैंक में भी बंधक बनाकर ऋण लिया गया

उन संपत्तियों को ही यूनियन बैंक में भी बंधक बनाकर ऋण लिया गया। रकम न चुकाने पर यूनियन बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया। बैंक जब बंधक बनाई गई संपत्तियों पर कब्जा लेने पहुंचा तब पता चला कि दूसरा बैंक उन्हें पहले ही जब्त कर चुका है। मामले में पहले सीबीआइ गाजियाबाद की एंटी करप्शन ब्रांच ने यूनियन बैंक की शिकायत पर 11 अप्रैल, 2020 को बैंक से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। ईडी ने मुकदमे को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी।

बिजली विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, 24 से ज्यादा बकायेदारों के काटे गए कनेक्शन

उत्तर प्रदेश के सभी जिले में बिजली चोरी के खिलाफ विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ताजा मामले में ग्रेटर नोएडा के दादरी में बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है। विभाग की छापेमार कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम और बिजली विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दो दर्जन से अधिक बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है।

परिवहन विशेष न्यूज

दादरी। जारचा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कलौंदा गांव में विजिलेंस टीम और बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली चोरी व बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बकायेदारों व बिजली चोरी करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया।

छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम व बिजली विभाग के अधिकारियों ने करीब 24 से अधिक बकायेदारों पर कार्रवाई करते हुए बिजली के कनेक्शन काटे।

इस दौरान टीम ने कई घंटे गांव में रहते हुए लोगों के बिजली कनेक्शन आदि की भी जांच की। विशेष अभियान के तहत विजिलेंस टीम में प्रभारी रामानंद कुशवाहा, उपखंड अधिकारी जयहिंद सिंह, जेई विमलेश आदि मौजूद रहे।

अभियान के दौरान बिजली विभाग ने छह पर दर्ज कराया मुकदमा

बिजली विभाग के उपखंड दादरी-दो के अंतर्गत आने वाले बिश्नुली में चैकिंग अभियान चलाया गया है। इसमें अवर अभियंता राजकुमार मौर्य, आशुतोष शुक्ला, संविदाकर्मी लोकेश राघव, राजकुमार, सचिन, रामकेश शामिल रहे।

अभियान के तहत कुल 46 लोगों के घरों का निरीक्षण किया गया, जिसमें छह जगह विद्युत चोरी पाई गई। पूर्व में बकाया होने पर काटे गए कनेक्शन जुड़े मिले जिस पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 18 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए जिसमें से पांच ने मौके पर 91 हजार रुपये जमा कराए।

तीन आरोपितों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज

दनकौर कस्बा और मंडी श्यामनगर में मंगलवार को अवर अभियंता अहमद मुस्तफा ने टीम के साथ बिजली चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुछ उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाया गया।

इसके अलावा करीब आठ लाख रुपए बकाया बिल जमा कराया गया। दनकौर कस्बे में तीन घरों में बिजली चोरी करने का मामला सामने आया। इसके चलते आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। अवर अभियंता ने कहा अभियान जारी रहेगा।

बिजली कटौती और ट्रिपिंग ने लोगों को किया परेशान

उधर, गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र में जगह-जगह मंगलवार को बिजली कटौती और नो ट्रिपिंग से लोग परेशान रहे। कौशांबी, कड़कड़ माडल, वसुंधरा सेक्टर चार, छह व सात, वैशाली सेक्टर दो, तीन व पांच, अभय खंड, एचआइजी कालोनी, डीएलएफ कालोनी, राजेंद्र नगर, सहित अन्य इलाकों में ट्रिपिंग की समस्या रही। शालीमार गार्डर में भी बिजली कटौती हुई।

स्थानीय निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि एक घंटे बिजली गुल रही। सूर्यनगर ब्लाक डी, चंद्रनगर, लाजपत नगर, इंद्रप्रस्थ, पंचशील कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी में एक से दो घंटे तक बिजली कटौती हुई। विद्युत निगम के मुख्य अभियंता अजय ओझा का कहना है कि निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है। फाल्ट की शिकायत मिलने पर उसे ठीक कर दिया गया था।

राव नरबीर सिंह जैसा हरियाणा में कोई नहीं, बनाया अनोखा रिकॉर्ड; जितनी बार विधायकी जीती, उतनी बार बने मंत्री

राव नरबीर सिंह हरियाणा के एक दिग्गज राजनेता हैं जिन्होंने विधायक के रूप में जितनी बार जीत हासिल की उतनी ही बार प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने। वह चौथी बार विधायक और चौथी बार मंत्री बने हैं। इस लेख में उनके राजनीतिक सफर मंत्री पदों पर उनके कार्यकाल और गुरुग्राम के विकास में उनके योगदान के बारे में विस्तार से जानें।

गुरुग्राम। अहीरवाल के दिग्गज राजनीतिज्ञों में से एक राव नरबीर सिंह ने जितनी बार विधायकी जीती, उतनी बार प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है। वह चौथी बार विधायक ही नहीं बल्कि चौथी बार मंत्री भी बने हैं। यही नहीं अलग-अलग मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मंत्री बने। वह ताऊ देवीलाल की सरकार में भी मंत्री रहे और उनकी चौथी पीढ़ी के दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ भी मंत्री रहे। ऐसा रिकॉर्ड फिलहाल प्रदेश के किसी अन्य नेता के नाम नहीं है।

प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर पर दूसरी बार कमल खिलाने वाले राव नरबीर सिंह ने चुनावी राजनीति की शुरुआत 1987 में जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र से की थी। लोकदल के टिकट पर उन्होंने वर्तमान में अहीरवाल के सबसे बड़े नेता और केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह को मात दी थी। इसका इनाम उन्हें ताऊ देवीलाल ने अपनी सरकार में गृह राज्यमंत्री बनाकर दिया था। उस समय उनकी उम्र केवल 26 साल थी।

बंसीलाल की सरकार में बने मंत्री

दूसरी बार वह 1996 में सोहना विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे व बंसीलाल की सरकार में परिवहन, सहकारिता एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बने। तीसरी बार 2014 में प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर से जीत हासिल कर मनोहर लाल सरकार में लोक निर्माण मंत्री बने। वर्ष 2019 में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इस बार फिर उन्हें भाजपा ने बादशाहपुर से ही टिकट दिया और उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। इस बार वह चौथी बार चौथे मुख्यमंत्री की सरकार में मंत्री बने हैं।

दादा राव मोहर सिंह भी रहे विधायक

राव नरबीर सिंह के दादा स्व. राव मोहर सिंह देश की आजादी से पहले दो बार 1942 एवं 1946 में पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। यही नहीं राव नरबीर सिंह के पिता स्व. महाबीर सिंह तीन बार विधायक रहे। महाबीर सिंह प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। राव नरबीर सिंह के चाचा भी विधायक रहे।

2014 से 2019 के बीच बनाई काम से पहचान

राव नरबीर सिंह लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं लेकिन विकास पुरुष के रूप में उनकी पहचान 2014 से 2019 के बीच में बनी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बेहतर केमेस्ट्री एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से बेहतर संबंध होने का लाभ गुरुग्राम को मिला। इफको चौक, सिग्नेचर टावर चौक, महाराणा प्रताप चौक, राजीव चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण 2014 से 2019 के बीच किया गया।

गुरुग्राम-सोहना हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस-वे, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, मेडिकल कालेज की योजना भी 2014 से 2019 के दौरान ही बनाई गई। उसी पांच साल के कार्यकाल को देखते हुए जनता ने उनके ऊपर इस बार भरोसा जताया है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इसी विषय पर जोर दिया कि यदि 2019 से 2024 तक वह मंत्री रहते तो गुरुग्राम बदहाल नहीं होता।

समर्थकों ने आतिशबाजी कर जताई खुशी

राव नरबीर सिंह को मंत्री बनाए जाने पर समर्थकों ने सिविल लाइन स्थित उनके आवास के सामने जमकर आतिशबाजी की। साथ ही मिठाइयां एक-दूसरे को खिलाकर खुशी प्रकट की। समर्थकों ने उम्मीद जाहिर की है कि अब गुरुग्राम में विकास की आंधी चलेगी।

क्या जम्मू-कश्मीर में नए युग की शुरूआत होगी

बलबीर पुंज

बुधवार (16 अक्तूबर) को उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में उप-राज्यपाल (एल.जी.) मनोज सिन्हा ने उमर के साथ 5 मंत्रियों को पद-गोपनीयता की शपथ दिलाई। उमर की पार्टी से...

बुधवार को उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में उप-राज्यपाल (एल.जी.) मनोज सिन्हा ने उमर के साथ 5 मंत्रियों को पद-गोपनीयता की शपथ दिलाई। उमर की पार्टी से सुरिंदर चौधरी उप-मुख्यमंत्री, तो निर्दलीय सतीश शर्मा मंत्री बनाए गए हैं।

यह एक अच्छी शुरूआत है। परंतु प्रश्न उठता है कि मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश में एक हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? यह स्थिति तब है, जब देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हिंदू प्रधान राज्यों केरल, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, बिहार, मणिपुर, पुडुचेरी और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्लिम और ईसाई समाज से भी रहे है। यही नहीं, हिंदू बहुल भारत में कई गैर-हिंदू राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपाल भी बन चुके हैं। सत्तारूढ़ नैशनल कांफ्रेंस (एन.सी.) ने अपने घोषणापत्र में जो 12 वायदे किए हैं, उनमें सूबे में धारा 370-35ए और राज्य के दर्जे को बहाल करने के साथ कश्मीरी पंडितों की घाटी में सम्मानजनक वापसी का वायदा भी शामिल है। मोदी सरकार ने इस बात को कई बार दोहराया है कि वह जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने को प्रतिबद्ध हैं।

इस सच्चाई से उमर भी अवगत हैं कि एल.जी. के पास कई शासकीय शक्तियां हैं और केंद्र के सहयोग के बिना, कई काम (राज्य दर्जा सहित) पूरे नहीं हो सकते। जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त, देश में सात और राज्य अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली दमन-दीव, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित हैं। वर्तमान समय में संभवतः दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, जहां की निर्वाचित सरकार और एल.जी. के बीच संबंध तल्ख है। इस संदर्भ में क्या जम्मू-कश्मीर की स्थिति दिल्ली जैसी हो सकती है? कांग्रेस की दिवंगत नेत्री शीला दीक्षित 1998-2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थीं। यदि केंद्र सरकार में उनकी पार्टी के नेतृत्व को छोड़ दें, तब मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित की 1998-2004 के कालखंड में राजनीतिक मतभेदों के बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी सरकार की अगुवाई में भाजपा नीत केंद्र सरकार से कोई तनातनी नहीं थी। इसमें बदलाव अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ('आप') की सरकार (2013 से अबतक) बनने के बाद आया, जो समन्वय के स्थान पर टकराव से देश की राजधानी में सरकार चला रही है।

इस प्रकार की अराजकतावादी राजनीति कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की देन है, जिन्होंने बिना वर्ष 2013 में किसी मंत्रिपद के अपनी ही सरकार के एक अध्यादेश को प्रैस-कांफ्रैंस में फाड़कर फैंक दिया था और अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में एल.जी. और 'आप' के बीच तनातनी मई 2014 के बाद मोदी सरकार में प्रारंभ हुई है। कांग्रेस नीत केंद्र सरकार द्वारा एल.जी. बनाए गए नजीब जंग (2013-16) के साथ भी 'आप' सरकार का रवैया कटु था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से अपनी पार्टी जैसा आचरण अपनाने का मशविरा दिया है। बकौल मीडिया रिपोर्ट, चुनाव जीतने के तुरंत बाद उमर ने स्पष्ट कर दिया था, ''हमें केंद्र के साथ समन्वय बनाकर चलने की जरूरत है। जम्मू-कश्मीर के कई मुद्दों का समाधान केंद्र से लड़ाई करके नहीं हो सकता...।'' यह देखना रोचक होगा कि मुख्यमंत्री उमर अपनी इस बात पर कितना खरा उतरते हैं?

एक पुराना मुहावरा है ''हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।'' क्या सच में सत्तारुढ़ एन.सी. अस्थायी धारा 370-35ए की वापसी चाहती है? अब्दुल्ला परिवार (फारुख-उमर) राजनीति में परिपक्व है। एक तो उन्हें मालूम है कि अब केंद्र में किसी भी दल की सरकार रहे, इन दोनों धाराओं की वापसी लगभग नामुमकिन है। सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ भी लंबी सुनवाई के बाद धारा 370-35ए के संवैधानिक परिमार्जन को हरी झंडी दे चुकी है। दूसरा यह कि इन दोनों प्रावधानों से क्या वाकई जम्मू-कश्मीर का कोई भला हुआ था? सच तो यह है कि धारा 370-35ए से कश्मीर की न केवल प्रगति रुक गई थी, बल्कि पाकिस्तान के सहयोग-वित्तपोषण से घाटी मध्यकालीन युग की ओर लौटने लगी थी।

क्या यह सच नहीं कि धारा 370-35ए के सक्रिय रहते घाटी में सभी आर्थिक गतिविधियां कुंद थीं विकास कार्यों पर लगभग अघोषित प्रतिबंध था, सेना-पुलिसबलों पर लगातार पत्थरबाजी होती थी, पर्यटक घाटी आने से कतराते थे, अलगाववादियों द्वारा मनमर्जी बंद बुला लिया जाता था, सिनेमाघरों पर ताला था, मजहबी आतंकवाद के साथ पाकिस्तान समर्थित अलगाववाद का वर्चस्व था, वातावरण 'पाकिस्तान जिंदाबाद' जैसे भारत-विरोधी नारों से दूषित था और शेष देश की भांति दलित-वंचितों के साथ आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों (आरक्षण सहित) पर डाका था।

ईमानदारी से विश्लेषण करने के बाद इस बात को धारा 370-35ए के पैरोकार भी नहीं झुठला सकते कि इन दोनों धाराओं की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर शेष भारत की तरह पिछले 5 वर्षों से गुलजार है। इस कॉलम में कई अवसरों पर हाल ही में कश्मीर की बदली स्थिति और सकारात्मकता का जिक्र किया है। जिनमें लालचौक की बढ़ती रौनक, नए-पुराने सिनेमाघरों के संचालन, जी-20 जैसा बड़ा वैश्विक सम्मेलन होना, देश-विदेश से लगभग सवा लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आना और हजारों-लाखों रोजगारों के मौके सृजन होना आदि शामिल हैं। अब्दुल्ला परिवार द्वारा अपनी पार्टी के घोषणापत्र में धारा 370-35ए को बहाल करने और कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक पुनर्वापसी का वादा एक-दूसरे के परस्पर विरोधी है। धारा 370-35ए ही वही विषबीज था, जिसने कश्मीर में 'काफिर-कुफ्र' जनित ईको-सिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

'देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ' 'पंजाब में भी सताने लगा डेंगू का डंक'

'डेंगू' को 'हड्डी तोड़ बुखार' भी कहा जाता है। इसमें 104 डिग्री तक तेज बुखार हो सकता है। इसका दिमाग पर असर पड़ कर यह प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। सिरदर्द, बदन दर्द, जोड़ों और पीठ में दर्द, भूख न लगने, जी मिचलाने तथा शरीर में लाल चकत्ते पड़ने, आंखों...

'डेंगू' को 'हड्डी तोड़ बुखार' भी कहा जाता है। इसमें 104 डिग्री तक तेज बुखार हो सकता है। इसका दिमाग पर असर पड़ कर यह प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। सिरदर्द, बदन दर्द, जोड़ों और पीठ में दर्द, भूख न लगने, जी मिचलाने तथा शरीर में लाल चकत्ते पड़ने, आंखों के पीछे दर्द, सूजन आदि की शिकायतें होती हैं। कभी-कभी रोगी के शरीर में आंतरिक रक्तस्राव भी होता है। इसके साथ ही कमजोरी तथा चक्कर भी आते हैं। इसमें प्लेटलैट्स घटने या ब्लड प्रैशर कम होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर पानी पीने और कुछ भी खाने में दिक्कत हो और बार-बार उल्टी आए तो डी-हाईड्रेशन का खतरा पैदा हो जाता है।

इस समय 'डेंगू' ने देश के कई राज्यों को चपेट में ले रखा है तथा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र आदि में 100 के लगभग मौतें भी हो चुकी हैं। पंजाब में भी 'डेंगू' का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गत सप्ताह जहां पंजाब में एक दिन में 'डेंगू' के लगभग 50-60 मामले आ रहे थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ कर प्रतिदिन 70 हो गई है। 'डेंगू' से बचाव के लिए शरीर के अंगों को ढांप कर रखना चाहिए। मच्छररोधी क्रीम का इस्तेमाल और व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है ठहरे हुए पानी को कीटाणु रहित करना। डेंगू से पीड़ित रोगी को पौष्टिक आहार फल, दाल, दूध आदि लेना चाहिए।

'डेंगू' बुखार 'एडीज' नामक मादा मच्छर के काटने से होता है। यह गंदे पानी की बजाय साफ और ठहरे हुए पानी में पनपता है। अतः पानी के बर्तन या टंकी को हर समय ढांप कर रखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसमें उचित कीटाणुनाशक का इस्तेमाल भी करना चाहिए। इसके अलावा गमलों, कूलरों, पुराने टायरों आदि में पानी जमा न होने दें, सफाई रखने और सरकार द्वारा समुचित फॉगिंग आदि नियमित रूप से करवाने से ही इस पर रोक लगाई जा सकती है।

– :सौजन्य :–

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV Drive the Future

एलजी एनर्जी को फोर्ड के लिए ईवी बैटरी की आपूर्ति का मिला सौदा

परिवहन विशेष न्यूज

एलजी एनर्जी सॉल्यूशन ने यूरोप में फोर्ड मोटर कंपनी के वाणिज्यिक वैन के विद्युतीकृत मॉडलों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसके साथ आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

अनुबंधों के तहत, एलजी एनर्जी सॉल्यूशन द्वारा फोर्ड को उसके इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वैन के लिए कुल 109 गीगावाट घंटे की बैटरी की आपूर्ति करने का अनुमान है, जिसकी शुरुआत 2026 से होगी तथा अनुबंध की अवधि चार से छह वर्ष तक होगी।

दोनों कंपनियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि वर्तमान फोर्ड मस्टैंग मैक-ई के लिए बैटरियों का उत्पादन 2025 में पोलैंड के बजाय एलजी एनर्जी सॉल्यूशन की मिशिगन सुविधा में किया जाएगा, ताकि व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि हो और IRA टैक्स क्रेडिट जैसी प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियों का लाभ उठाया जा सके।

एलजी एनर्जी सॉल्यूशन के सीईओ डेविड किम ने कहा, "ये समझौते, चरम उपयोगकर्ता वातावरण को संभालने के लिए डिजाइन की गई अभिनव बैटरी प्रौद्योगिकियों के साथ वाणिज्यिक वाहनों को शक्ति प्रदान करने में हमारे अनुभव और विशेषज्ञता को प्रमाणित करते हैं।"

"अपनी स्थानीय उत्पादन क्षमता का लाभ उठाते हुए, हम यूरोपीय बाजार में नेतृत्व हासिल करेंगे और उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपने ग्राहकों को बेजोड़ मूल्य प्रदान करेंगे, जो विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करते हैं।"

बजाज ऑटो अपनी ब्राजीलियाई सहायक कंपनी में 10 मिलियन डॉलर का करेगी निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की अग्रणी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों में से एक बजाज ऑटो लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली ब्राजीलियाई सहायक कंपनी बजाज डो ब्रासिल कॉमर्सियो डी मोटोसाइकलटस लिमिटेड (₹बजाज ब्राजील₹) में 10 मिलियन डॉलर तक निवेश करने की योजना की घोषणा की है। आज बुधवार, 16 अक्टूबर को आयोजित एक बैठक के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस निर्णय को मंजूरी दी गई।

वर्तमान विनिमय दरों पर लगभग ₹84 करोड़ के बराबर अतिरिक्त पूंजी निवेश का उद्देश्य व्यवसाय विस्तार को वित्तपोषित करना और ब्राजील में बढ़ते परिचालन की जरूरतों को पूरा करना है। यह निवेश व्यवसाय की आवश्यकताओं और योजनाओं के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

31 मार्च, 2022 को निगमित बजाज ब्राज़ील ने ब्राज़ील के मोटरसाइकिल बाज़ार में आशाजनक वृद्धि दिखाई है। जून 2024 में, सहायक कंपनी ने मनौस मुक्त व्यापार क्षेत्र में अपनी खुद की विनिर्माण सुविधा शुरू की, जिसकी वार्षिक क्षमता एकल शिफ्ट के आधार पर 20,000 इकाइयों की है। कंपनी वर्तमान में ब्राज़ील में 'डोमिनार' ब्रांड के तहत मोटरसाइकिल बेचती है।

30 सितंबर, 2024 को समाप्त होने वाली पिछली चार तिमाहियों के आधार पर बजाज ब्राज़ील के परिचालन का आकार लगभग ₹250 करोड़ था, जो लगभग 9,000 मोटरसाइकिलों की बिक्री से प्राप्त हुआ।

यह रणनीतिक निवेश बजाज ऑटो की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने और ब्राजील के बाजार में विकास के अवसरों का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कदम से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कंपनी की स्थिति मजबूत होने और इसकी अंतरराष्ट्रीय विकास रणनीति को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

इस निवेश के बाद बजाज ऑटो लिमिटेड के पास बजाज ब्राज़ील का 100% स्वामित्व बना रहेगा।

बजाज ऑटो ने कई विदेशी बाजारों में अपने परिचालन का विस्तार किया है। कंपनी की अंतरराष्ट्रीय रणनीति उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित रही है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सफलता की अलग-अलग डिग्री रही है।

बजाज ऑटो द्वारा अपने ब्राजील परिचालन में अतिरिक्त 10 मिलियन डॉलर का निवेश करने के हाल के निर्णय से पता चलता है कि कंपनी को विकास की संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन यह भी संकेत मिलता है कि मजबूत उपस्थिति स्थापित करने के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता है।

सर्वोटेक और एनस्मार्ट पावर ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए मिलाया हाथ

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में ईवी चार्जर निर्माता सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने यूके स्थित एनस्मार्ट पावर के साथ एकमात्र वितरण समझौता किया है, जो महत्वपूर्ण बिजली, सौर और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी है। इस समझौते का उद्देश्य पूरे यूके में ईवी चार्जर्स के लिए वितरण नेटवर्क में सुधार करना और उत्तरी अमेरिका में विस्तार करना है।

इस साझेदारी का उद्देश्य इन बाजारों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। इसके लिए सर्वोटेक के चार्जिंग समाधानों को एनस्मार्ट पावर की ऊर्जा वितरण विशेषज्ञता के साथ जोड़ा गया है। साथ मिलकर, वे एक विश्वसनीय चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का इरादा रखते हैं, जो अधिक टिकाऊ परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है और कुशल, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक रमन भाटिया ने कहा कि यह सहयोग उनकी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत करने और स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक बाजारों में अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जो इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए चार्जिंग अनुभव को बढ़ाएगा।

एनस्मार्ट पावर के प्रबंध निदेशक डेनिज़ टैनर ने साझेदारी के लिए उत्साह व्यक्त किया, रमन भाटिया के साथ दीर्घकालिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सहयोग का उद्देश्य बौद्धिक संपदा और विचारों को साझा करना है, जिससे ईवी चार्जिंग समाधान अधिक सुलभ और किफायती बन सकें। इस पहल का उद्देश्य ईवी मालिकों के लिए रेंज के बारे में चिंताओं को कम करना और यूके और उसके बाहर प्रौद्योगिकी और चार्जिंग गति में प्रगति का समर्थन करना है।

सितम्बर 2024 में कैसी रही हैचबैक कार की मांग, टॉप-5 में शामिल हुई स्विफ्ट, बलेनो और वैगन आर

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के साथ ही कई और सेगमेंट की कारों की मांग रहती है। लेकिन बीते महीने हैचबैक सेगमेंट की कारों की बिक्री कैसी रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक September 2024 के दौरान देश भर में किन Hatchback Cars की बिक्री हुई है। Top-5 लिस्ट में किस कंपनी की कौन सी कार शामिल हुई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। अगस्त महीने में भी देशभर में बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री हुई है। लेकिन हैचबैक सेगमेंट की कारों की बिक्री में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान कुल कितनी बिक्री हुई है। Top-5 में कौन सी कारें शामिल हुई हैं। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

Maruti Swift

मारुति सुजुकी की स्विफ्ट बिक्री के मामले में पहले नंबर पर रही। इस हैचबैक कार की September 2024 के दौरान कुल 16241 यूनिट्स की बिक्री हुई। September 2023 में इसकी कुल 14703 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। बिक्री के मामले में इस कार की बीते महीने में 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

Maruti Baleno

बीते महीने के दौरान सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली Hatchback Cars में मारुति की बलेनो दूसरे नंबर पर रही। कंपनी ने इस हैचबैक कार की 14292 यूनिट्स की बिक्री September 2024 में कह है। जबकि पिछले महीने इसी अवधि दौरान इस कार की कुल 18413 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक बलेनो की बिक्री में 22 फीसदी की कमी आई।

Maruti Wagon R

मारुति की ओर से वैगन आर को हैचबैक सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। September 2024 के दौरान भी यह कार अन्य Hatchback Cars के मुकाबले सबसे ज्यादा पसंद की गई और बिक्री के मामले में यह तीसरे नंबर पर रही। मारुति की वैगन आर की बीते महीने में कुल 13339 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान कंपनी ने 16250 यूनिट्स की बिक्री की थी। आंकड़ों के मुताबिक इसकी बिक्री में 18 फीसदी की कमी आई है।

Maruti Alto

मारुति ऑल्टो की बिक्री में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन अभी भी यह भारत में काफी पसंद की जाती है। बीते महीने इस हैचबैक कार की कुल 8655 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि पिछले साल इस कार को 7791 ग्राहकों ने खरीदा था।

Hyundai Nios Grand i10

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई की हैचबैक कार आई-10 को भी बीते महीने के दौरान 5103 लोगों ने खरीदा है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान इसे 5223 लोगों ने खरीदा था। आंकड़ों के मुताबिक इसकी बिक्री में दो फीसदी की कमी दर्ज की गई है।

अन्य का कैसा रहा हाल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Top-5 के अलावा बीते महीने जिन हैचबैक कारों की बिक्री हुई है उनमें Tata Tiago, Toyota Glanza, Maruti Celerio और Tata Altroz हैं।

टाटा मोटर्स की सहायक कंपनियों ने डीलरों को वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए एचएसबीसी इंडिया के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स की सहायक कंपनियों, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (टीपीईएम) और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) ने अपने यात्री और इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों के लिए वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए एचएसबीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य डीलरों को एचएसबीसी इंडिया की आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण विशेषज्ञता के माध्यम से कार्यशील पूंजी तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धी शर्तों के तहत वित्तपोषण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस सहयोग से डीलरों को बढ़ते यात्री वाहन बाजार में अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के उपाध्यक्ष धीमान गुप्ता ने उभरते ऑटोमोटिव क्षेत्र में डीलर भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एचएसबीसी इंडिया के साथ वित्तपोषण कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यशील पूंजी तक उनकी पहुँच बढ़ाकर और व्यावसायिक संचालन को सुविधाजनक बनाकर डीलरों का समर्थन करना है।

एचएसबीसी इंडिया में बिजनेस बैंकिंग के कंट्री हेड गौरव सहगल ने यात्री और इलेक्ट्रिक वाहन डीलर नेटवर्क के लिए वित्तपोषण विकल्पों के विस्तार में इस साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह सहयोग स्वच्छ और कुशल परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के साझा लक्ष्य को दर्शाता है।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी भूमिका के लिए मशहूर टाटा मोटर्स पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक सहित कई ईंधन प्रकारों में वाहनों की एक श्रृंखला पेश करती है। कंपनी का पोर्टफोलियो मोबिलिटी सेक्टर में विभिन्न उपभोक्ता जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

लॉन्च से पहले बजाज ने दिखाई नई पल्सर N125, नए रंग के साथ मिली फीचर्स की जानकारी

देश की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता Bajaj की ओर से भारतीय बाजार में कई बाइक स को ऑफर किया जाता है। कंपनी जल्द ही अपनी नई बाइक Bajaj Pulsar N125 New Model 2024 को लॉन्च कर ने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर जारी टीजर में किस तरह के फीचर्स की जानकारी दी गई है। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख दो पहिया निर्माता Bajaj की ओर से जल्द ही नई Bajaj Pulsar N125 को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले कंपनी ने सोशल मीडिया पर नया टीजर जारी किया है। जिसमें बाइक की जानकारी के साथ ही कुछ फीचर्स की जानकारी भी मिल रही है। बाइक में किस तरह के फीचर्स को दिया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Bajaj ने दिखाई नई Pulsar N125

बजाज की ओर से पल्सर एन125 को पेश कर दिया है। कंपनी की ओर से बाइक का नया टीजर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी हुए टीजर में इसके कई फीचर्स की जानकारी मिल रही है।

क्या होगी खासियत

सोशल मीडिया पर बाइक के टीजर को जारी किया गया है। इसमें बाइक को पूरी तरह से दिखा दिया गया है। बाइक को कई रंगों के विकल्प के साथ लाया जाएगा। टीजर में जिस यूनिट को दिखाया गया है वह ग्लॉसी रंग में है और उसमें हनीकॉम्ब स्टाइल के ग्राफिक्स भी दिए गए हैं। साथ ही बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी हेडलाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक, फ्रंट फॉर्क्स पर प्लास्टिक कवर, स्प्लिट सीट्स, सिल्वर रंग की ग्रैब रेल को दिया जाएगा।

कितना दमदार इंजन

अभी सिर्फ बाइक को सिर्फ पेश किया गया है। 125 सीसी सेगमेंट में आने वाली इस बाइक में सामान्य पल्सर 125 से ज्यादा ताकतवर इंजन दिया जाएगा। उम्मीद है कि इसमें 125 सीसी इंजन से 11.8 पीएस की पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है।

3एस इंडस्ट्रीज ने पटना में लॉन्च किया 5 बैटरी वाला मॉडल पंच भारत

परिवहन विशेष न्यूज

3एस इंडस्ट्रीज कंपनी "भारत ई-रिक्शा और पंच भारत" ब्रांड नाम से ई-रिक्शा व ई-कार्ट बनाती है।

कंपनी के निदेशक अंकित मेंदीरत्ता ने बताया कि पिछले महीने पटना में सुनैना इंटरप्राइजेज के माध्यम से पंच भारत को लॉन्च किया गया। लॉन्च के साथ ही पटना के बाजार में पंच भारत की जबरदस्त बिक्री शुरू हो गई। जिसके लिए कंपनी पटना की जनता का आभार जताती है। साथ ही सुनैना इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर श्री रवि जी का भी आभार जताती है।

कंपनी की मार्केटिंग निदेशक रितुपर्णा ने बताया कि इस उत्पाद की काफी समय से लगातार मांग थी, इसलिए कंपनी ने शानदार, दमदार और किफायती कीमत पर पंच भारत तैयार किया है। कंपनी जल्द से जल्द अपने नेटवर्क का विस्तार करने की कोशिश कर रही है, ताकि ग्राहकों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण ई-रिक्शा उपलब्ध कराई जा सके।

3एस इंडस्ट्रीज, जिसमें 3एस का मतलब है "सहयोग, संगठन व सफलता" और कंपनी ₹फ़ादरहुड ऑफ गॉड और ब्रदरहुड ऑफ मैनर₹ के सिद्धांत पर आधारित है।

उत्तरी भारत को एक और साल ख़राब वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़े रहे हैं

विजय गर्ग

त्वरित और निरंतर प्रयासों के बिना, उत्तरी भारत को एक और वर्ष बिगड़ती वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ेगा, जिससे लाखों लोग खराब वायु गुणवत्ता से जूझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता पराली जलाने को नियंत्रित करने में विफलता के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 3 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान दी गई अदालत की फटकार में जमीनी स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया गया और सवाल उठाया गया कि आयोग ने फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू क्यों नहीं किया है।

त्वरित और निरंतर प्रयासों के बिना, उत्तरी भारत को एक और वर्ष बिगड़ती वायु गुणवत्ता का सामना करना पड़ेगा, जिससे लाखों लोग खराब वायु गुणवत्ता से जूझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदानकर्ता पराली जलाने को नियंत्रित करने में विफलता के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 3 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान दी गई अदालत की फटकार में जमीनी स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया गया और सवाल उठाया गया कि आयोग ने फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू क्यों नहीं किया है। पराली जलाना, विशेषकर उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, वर्षों से एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती रही है। खेती में बढ़ते मशीनीकरण, संयुक्त हार्वेस्टर के उपयोग, श्रमिकों की कमी और बढ़ती श्रम लागत के कारण किसान अक्सर धान और गेहूं की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने का सहारा लेते हैं। धान की फसल के बाद अक्टूबर और नवंबर में प्रचलित इस प्रथा के परिणामस्वरूप वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कण निकलते हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक वायु गुणवत्ता में योगदान करते हैं। सीएक्यूएम की सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने में आयोग की असमर्थता पर व्यापक निराशा को दर्शाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के लिए तीन साल पहले स्थापित किए जाने के बावजूद, सीएक्यूएम की धीमी गति और ठोस परिणामों की कमी के लिए आलोचना की गई है। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि आयोग की बैठक हर तीन महीने में केवल एक बार होती है, पराली जलाने जैसे बार-बार आने वाले संकट से निपटने के लिए यह बैठक अपर्याप्त मानी जाती है। इसके अलावा, आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से केवल 82 निर्देश जारी किए हैं, एक संख्या जिसे अदालत ने समस्या के पैमाने से निपटने के लिए अपर्याप्त बताया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाई गई एक महत्वपूर्ण चिंता दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रभावित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के भीतर पर्याप्त कर्मचारियों की कमी है। अदालत ने आदेश दिया कि निगरानी और प्रवर्तन क्षमताओं में सुधार के लिए इन रिक्त पदों को 30 अप्रैल, 2025 तक भरा जाए। जमीनी स्तर पर उपायों को लागू करने के लिए प्रभावी स्टाफिंग महत्वपूर्ण है, खासकर उन किसानों से निपटने के दौरान जो अपने खेतों को खाली करने के लिए त्वरित और लागत प्रभावी तरीके के रूप में फसल अवशेष जलाने पर निर्भर हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद, पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले साल अकेले, विकल्प तलाशने के लिए किसानों के साथ जुड़ने के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी, पंजाब में पराली जलाने की 33,000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं। राज्य सरकारों और सीएक्यूएम के बीच समन्वित प्रयास की कमी ने सर्दियों के महीनों के दौरान प्रदूषण संकट को और बढ़ा दिया है। पराली को एक संसाधन में बदलना: जबकि ध्यान सीएक्यूएम की विफलताओं और पंजाब जैसे राज्यों में जारी चुनौतियों पर केंद्रित है, उत्तर प्रदेश इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है कि कैसे पराली को अधिक टिकाऊ ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। राज्य ने उन पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया है जो पराली को ऊर्जा संसाधन और प्राकृतिक उर्वरक में बदल देती हैं, जिससे पर्यावरण और कृषि समुदाय दोनों को लाभ होता है। इस परिवर्तन की कुंजी कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना रही है जो परिवर्तित होते हैंफसल अवशेषों को ऊर्जा और उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदलें। इस दृष्टिकोण ने न केवल पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित किया है, बल्कि किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनाया है, जो सीबीजी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में पराली बेचते हैं। इस तरह, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पराली एक बोझ से हटकर एक मूल्यवान संपत्ति बन गई है। पिछले वर्ष तक, उत्तर प्रदेश दस परिचालन संयंत्रों के साथ सीबीजी उत्पादन में देश में अग्रणी था। वर्तमान में, 24 सीबीजी इकाइयाँ सक्रिय हैं, और अन्य 93 निर्माणाधीन हैं। राज्य का लक्ष्य जल्द ही 100 से अधिक सीबीजी संयंत्र चालू करना है, इस लक्ष्य का केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने समर्थन किया है। मार्च 2024 की घोषणा के दौरान, उन्होंने 2025 तक अपने जैव-कोयला और बायोडीजल उत्पादन को दोगुना करने की राज्य की योजना पर प्रकाश डाला। उत्तर प्रदेश में सीबीजी उत्पादन की सफलता को उत्तर प्रदेश राज्य जैव-ऊर्जा नीति 2022 द्वारा बढ़ावा दिया गया है, जो इसके लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करता है। कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके जैव-सीएनजी और सीबीजी इकाइयों की स्थापना। नीति का लक्ष्य हर जिले में सीबीजी संयंत्र स्थापित करना, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए पराली प्रबंधन के लिए स्थानीय समाधान प्रदान करना है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 8 मार्च, 2023 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा धुरियापार, गोरखपुर में सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन था। 165 करोड़ रुपये में बना यह प्लांट प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन पुआल, 20 मीट्रिक टन प्रेस मड और 10 मीट्रिक टन गोबर का प्रसंस्करण करता है। यह 20 मीट्रिक टन बायोगैस और 125 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन करता है, जो रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करते हुए उच्च कृषि उपज में योगदान देता है। यह पहल किसानों को अपने आय स्रोतों में विविधता लाने और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देती है। पराली जलाने की प्रथा को कम करके राज्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विश्वास जताया है कि बायो-कोयला और बायोडीजल के बढ़े हुए उत्पादन से अगले पांच वर्षों में क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की सीएक्यूएम की आलोचना पराली जलाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण खोजने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है जो पर्यावरणीय चिंताओं और किसानों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों दोनों का सम्मान करता है। पराली को संसाधन में बदलने का उत्तर प्रदेश का मॉडल इसी तरह के मुद्दों से जूझ रहे अन्य राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम कर सकता है। हालाँकि, व्यापक चुनौती बनी हुई है: ऐसे समाधानों को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए लगातार नीति समर्थन, पर्याप्त संसाधन और किसानों के साथ सीधे जुड़ने की इच्छा की आवश्यकता होती है। सीएक्यूएम को अपने दृष्टिकोण में सुधार करने और राज्य सरकारों को 2025 तक रिक्त पदों को भरने के लिए अदालत का निर्देश जवाबदेही की दिशा में एक कदम है। फिर भी, असली परीक्षा इन निर्देशों को अमल में लाने में होगी, इससे पहले कि एक और सर्दी दिल्ली-एनसीआर के आसमान में परिचित, दमघोंटू धुंध को वापस ला दे। सवाल यह है कि क्या सीएक्यूएम, राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, यूपी में देखे गए जैसे नवीन समाधानों को अपना सकता है और अपना सकता है। त्वरित और निरंतर प्रयासों के बिना, इस क्षेत्र में एक और वर्ष वायु गुणवत्ता में गिरावट का सामना करने का जोखिम है, जिससे लाखों लोगों को निष्क्रियता के स्वास्थ्य परिणामों से जूझना पड़ेगा।

राय

ब्यूटी केयर और अन्य जीवनशैली में नौकरी के अवसर और करियर

विजय गर्ग

इस दुनिया में हर कोई अपने मूल स्थान, लिंग, वित्तीय स्थिति, जाति या पंथ की परवाह किए बिना दूसरों की नजरों में सुंदर या आकर्षक और फैशनेबल दिखना पसंद करता है और इसे अपनी स्थिति के अनुसार बनाए रखने की कोशिश करता है। आज की पीढ़ी के लिए ऐसा नहीं है, पुराने समय में भी खूबसूरत दिखने का खास ख्याल रखा जाता था। अंतर केवल इतना है कि उस समय जागरूक प्रयास केवल कुलीनों द्वारा ही किये जाते थे और जनता सचेत रूप से इसके पीछे नहीं थी। लेकिन अब फैशन और ब्यूटी केयर आम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इससे कॉस्मेटोलॉजी का क्षेत्र फल-फूल रहा है, जिसे आम तौर पर इसके सभी पहलुओं में सौंदर्य देखभाल और फैशन के रूप में जाना जाता है।

'ब्यूटी केयर' जो लोगों को सर्वश्रेष्ठ दिखने में मदद करता है, उन आकांक्षी लोगों के लिए एक क्षेत्र है जो सुंदरता पर नज़र रखते हैं और लोगों के साथ बातचीत का आनंद लेते हैं। काम का माहौल तेजी से प्रतिस्पर्धी और पेशेवर होने और पुरुषों और महिलाओं के बीच स्वास्थ्य और सौंदर्य के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, अच्छी तरह से तैयार और आकर्षक दिखने की आवश्यकता आज की दुनिया में अधिक महत्व रखती है। इसके परिणामस्वरूप सौंदर्य उत्पादों और सौंदर्य उपचारों में वृद्धि हुई है, जिससे सौंदर्य देखभाल एक तेजी से बढ़ते और आकर्षक करियर में बदल गई है।

इस करियर के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि सफलता का अभ्यास करने वाले की उम्र से कोई संबंध नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है और सफल हो सकता है। जैसे-जैसे स्वाद और सुंदरता के रुझान में छोटे-छोटे बदलाव होते रहते हैं, ब्यूटीशियन/सौंदर्य देखभाल पेशेवर का मूल काम वही रहता है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास काम करने के लिए कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं जैसे हेयर स्टाइलिंग, सौंदर्यशास्त्र, मैनीक्योर, पेडीक्योर और इलेक्ट्रोलिसिस आदि।

सौंदर्य देखभाल में काम करने के लिए इतने सारे क्षेत्रों के साथ, विशेषज्ञ पांच सितारा होटलों के शानदार सैलून से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और छोटे पार्लरों तक के ब्यूटी पार्लरों में काम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में एक नौसिखिया प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने और नए विकास के संपर्क में रहने के लिए एक अनुभवी ब्यूटीशियन के अधीन काम कर सकता है। अपेक्षित अनुभव प्राप्त करने के बाद, कोई भी अपना स्वयं का ब्यूटी सैलून या क्लिनिक स्थापित कर सकता है। किसी को स्वास्थ्य क्लबों और संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है या कॉस्मेटोलॉजी स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है। वे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और वेब प्रकाशकों में सलाहकार कॉस्मेटोलॉजी विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकते हैं।

प्रतिदिन कुछ पढ़ना तेज़ दिमाग की कुंजी

क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन कुछ मिनट पढ़ने से आपका मूड अच्छा हो सकता है, आपका दिमाग तेज़ हो सकता है और आपको तनाव से बचने में मदद मिल सकती है? चाहे आपको कोई उपन्यास, लेख, या यहाँ तक कि एक पत्रिका पढ़ना पसंद हो, पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। पढ़ने को एक आदत क्यों न बनाएं? इस लेख में, हम हर दिन पढ़ने के विभिन्न कारणों का पता लगाएंगे। प्रतिदिन पढ़ने के कारण दिमाग को उत्तेजित करने में मदद करता है क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन पढ़ने से आपका मस्तिष्क सक्रिय और मजबूत रहता है? अध्ययनों से पता चला है कि, यदि आप मानसिक रूप से व्यस्त हैं, तो यह अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी स्थितियों को धीमा करने या रोकने में मदद करता है। जैसे हमारी मांसपेशियों को फिट रहने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपके मस्तिष्क को तेज रहने के लिए गतिविधि की आवश्यकता होती है। चाहे वह पहेलियाँ सुलझाना हो, शतरंज जैसे खेल खेलना हो, या बस पढ़ना हो, ये गतिविधियाँ आपके दिमाग को स्वस्थ रखने और स्मृति हानि की संभावना को कम करने में मदद करती हैं। आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है जब आप कोई पुस्तक, लेख, समाचार पत्र या पत्रिका पढ़ते हैं, तो आपको अत्यधिक ज्ञान प्राप्त होता है। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वह आपके दिमाग में नई जानकारी जोड़ता है, और आप कभी नहीं जानते कि वह जानकारी आपके लिए कब उपयोगी हो सकती है। आप जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप जीवन में आने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से तैयार होंगे। साथ ही, भले ही आप अपनी नौकरी, पैसा या स्वास्थ्य जैसी चीजें खो दें, लेकिन आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह आपके साथ रहता है और इसे कभी भी छीना नहीं जा सकता। तनाव कम करने में मदद करता है आज की दुनिया में लोग बहुत अधिक तनाव में हैं और तनाव कम करने के लिए पढ़ना एक शक्तिशाली उपकरण है। चाहे वह एक मनोरम उपन्यास हो जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है या एक आकर्षक लेख जो आपको उस पल में खींचता है, किसी कहानी में खुद को खो देने से तनाव दूर हो सकता है। जब आप कहानियों की काल्पनिक दुनिया में डूब जाते हैं, तो आप स्कूल, व्यक्तिगत रिश्तों और दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं और तनाव से मानसिक रूप से बच जाते हैं, जिससे आप आराम कर सकते हैं और तरोताजा हो सकते हैं। आपकी शब्दावली का विस्तार करने में मदद करता है यदि आप हर दिन नए शब्द सीखना चाहते हैं, तो पढ़ना अधिक शब्द सीखने का सबसे अच्छा तरीका है जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग कर सकते हैं। नए शब्द सीखने से न केवल आपको अच्छा बोलने में मदद मिलती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, करियर की संभावनाएं बढ़ती हैं और आप अधिक स्पष्टवादी बनते हैं। इसके अतिरिक्त, पढ़ना उन नए शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो नई भाषाएँ सीख रहे हैं क्योंकि पढ़ने से गैर-देशी वक्ताओं को संदर्भ में उपयोग किए गए शब्दों को देखकर उनके प्रवाह में सुधार करने में मदद मिलती है। आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करता है क्या आप महत्वपूर्ण तारीखें या जानकारी भूल जाते हैं? यदि हां, तो पढ़ना आपकी याददाश्त को बेहतर बनाने का एक तरीका है। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो आपको विभिन्न पात्र, उनकी पृष्ठभूमि और कहानी के उतार-चढ़ाव याद आते हैं। यह व्यायाम आपके मस्तिष्क को मजबूत बनाता है और आपको चीजों को बेहतर ढंग से याद करने में मदद करता है, साथ ही आपके मूड में भी सुधार करता है। उदाहरण के लिए, एक रहस्यमय उपन्यास में, आपको ऐसे सुराग याद आ सकते हैं जो मामले को सुलझाने की ओर ले जाते हैं। जबकि, एक फंतासी में, आप विभिन्न पात्रों और उनके कारनामों पर नज़र रखते हैं। आपका फोकस और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है आज की दुनिया में, हर किसी का ध्यान दिन-ब-दिन कम होता जा रहा है क्योंकि लोग एक साथ कई काम निपटाते हैं। इस लगातार मल्टीटास्किंग से तनाव बढ़ सकता है और उत्पादकता कम हो सकती है। हालाँकि, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो आपका ध्यान पूरी तरह से कहानी पर केंद्रित होता है, जिससे आप ध्यान भटकने से बच जाते हैं और विवरणों में डूब जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि, स्कूल जाने से पहले केवल 15-20 मिनट पढ़ने से आपको कक्षाओं के दौरान बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है? लेखन कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है विभिन्न पुस्तकों, लेखों या कहानियों को पढ़ने से आप विभिन्न प्रकार के लेखन से परिचित होते हैंशैलियाँ, शब्दावली और विचार व्यक्त करने के तरीके। यह आपको वाक्यों की संरचना करना, विचार विकसित करना और सही शब्दों का चयन करना सीखने में मदद करता है। यह सीखकर कि अनुभवी लेखक अपनी कहानियाँ कैसे गढ़ते हैं और जानकारी को कैसे समझाते हैं, आप अपने लेखन में सुधार करना शुरू करते हैं। इसके अलावा, जितना अधिक आप पढ़ेंगे, उतना ही अधिक आपको अपनी कहानियाँ लिखने के लिए रचनात्मक विचार मिलेंगे। मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल बनाने में मदद करता है क्या होगा यदि पढ़ना आपके समस्या-समाधान कौशल को निखारने का सबसे प्रभावी उपकरण है? क्या आपको आश्चर्य है कि एक साधारण किताब आपके सोचने के तरीके को कैसे बदल सकती है? पढ़ना मस्तिष्क को आलोचनात्मक सोच और समझ में संलग्न करके मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल बनाने में मदद करता है। जैसे-जैसे पाठक जटिल कथानकों, तर्कों या डेटा का विश्लेषण करते हैं, वे मुख्य विवरणों की पहचान करने की कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि विभिन्न विचार और कथानक कैसे जुड़ते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को देखते हैं, जो उनके सोच कौशल को बेहतर बनाने में मदद करेगा। तल - रेखा हर दिन बस कुछ मिनट पढ़ने से आपका मूड अच्छा हो सकता है, आपका दिमाग तेज़ हो सकता है और तनाव कम हो सकता है। यह आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखने, आपके ज्ञान को बढ़ाने और आपकी शब्दावली में सुधार करने में मदद करता है। पढ़ने से आपको चीजें बेहतर ढंग से याद रखने, ध्यान केंद्रित रहने और एक बेहतर लेखक बनने में भी मदद मिलती है। साथ ही, यह आपको विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों के बारे में गंभीर रूप से सोचने पर मजबूर करके आपके विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित कर सकता है। कुल मिलाकर, पढ़ने को दैनिक आदत बनाने से आपके मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को बहुत फायदा हो सकता है।

द वॉकिंग लाइब्रेरी

विजय गर्ग

वॉकिंग लाइब्रेरी एक रचनात्मक और सहयोगात्मक परियोजना है जो साहित्य, पैदल यात्रा और पर्यावरण संबंधी जुड़ाव को जोड़ती है। 2012 में कलाकार डी हेडन और मिशा मायर्स द्वारा विकसित, यह परियोजना एक सरल लेकिन शक्तिशाली अवधारणा के साथ शुरू हुई: चलने के कार्य से संबंधित पुस्तकों की एक मोबाइल लाइब्रेरी बनाना। विचार यह था कि चलने की भौतिक यात्रा को पढ़ने की बौद्धिक यात्रा के साथ जोड़ा जाए, जो चिंतन, बातचीत और खोज के लिए एक अद्वितीय स्थान प्रदान करे। उत्पत्ति और उद्देश्य वॉकिंग लाइब्रेरी का जन्म यह जानने की इच्छा से हुआ था कि चलना हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया के साथ जुड़ने के तरीके को कैसे आकार देता है। हेडन और मायर्स का मानना था कि पैदल चलने से परिदृश्यों को अनुभव करने और समझने के नए तरीके खुलते हैं, चाहे वे ग्रामीण, शहरी या कहीं बीच के हों। किताबों के साथ चलने को जोड़कर, उन्होंने सहभागी कला का एक रूप तैयार करते हुए लोगों और उनके परिवेश के बीच गहरे संबंधों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। परियोजना प्रतिभागियों को निर्देशित वॉक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है, जिसके दौरान वे उन पुस्तकों का चयन करते हैं जिन्हें वॉक की थीम के आधार पर सोच-समझकर तैयार किया गया है। ये किताबें सिर्फ चलने के बारे में नहीं हैं, बल्कि उन परिदृश्यों और विचारों के बारे में भी हैं जो चलने से उत्पन्न हो सकते हैं। प्रत्येक यात्रा के साथ पुस्तकालय बदलता है, क्योंकि संदर्भ के आधार पर किताबें जोड़ी जाती हैं या बदली जाती हैं। जैसे-जैसे क्यूरेटर, प्रतिभागी और यहां तक कि राहगीर भी नए शीर्षक सुझाते हैं, संग्रह बढ़ता जाता है। एक रचनात्मक अभ्यास के रूप में चलना चलना लंबे समय से रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। पूरे इतिहास में लेखकों, दार्शनिकों और कलाकारों जैसे हेनरी डेविड थोरो, वर्जीनिया वूल्फ और फ्रेडरिक नीत्शे ने चलने की प्रेरणादायक शक्ति के बारे में बात की है। वॉकिंग लाइब्रेरी इस परंपरा पर आधारित है, जिसमें यह पता लगाया गया है कि चलने की लय विचार और रचनात्मकता को कैसे उत्तेजित कर सकती है। यह केवल शारीरिक गतिविधि के बारे में नहीं है, बल्कि बौद्धिक और भावनात्मक यात्राओं के बारे में भी है, जो तब सामने आती हैं जब प्रतिभागी अपने परिवेश और अपने साथ लाए गए पाठ दोनों के साथ जुड़ते हैं। परियोजना के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि किताबें और घूमना दोनों अन्वेषण के कार्य हैं। चलना जिज्ञासा और सावधानी को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रतिभागियों को उन विवरणों पर ध्यान देने की अनुमति मिलती है जिन्हें वे अन्यथा अनदेखा कर सकते हैं। इसी तरह, पढ़ने से नई दुनिया और दृष्टिकोण खुलते हैं। वॉकिंग लाइब्रेरी इन अनुभवों को जोड़ती है, एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां वॉकर और पाठक दोनों साहित्य, स्थान और स्वयं के बीच संबंधों पर विचार कर सकते हैं। समुदाय और पर्यावरण सहभागिता वॉकिंग लाइब्रेरी अक्सर साइट-विशिष्ट होती है, जिसे उस विशेष परिदृश्य या घटना के अनुरूप बनाया जाता है जहां इसे आयोजित किया जाता है। यह दुनिया भर के विभिन्न कला उत्सवों, निवासों और सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई दिया है। पुस्तकों का चयन आम तौर पर सैर के विशिष्ट वातावरण से संबंधित होता है, चाहे वह ग्रामीण इलाका हो, शहरी पड़ोस हो, या कोई ऐतिहासिक स्थल हो। प्रत्येक स्थान के अनूठे गुणों पर ध्यान आकर्षित करके, परियोजना प्रतिभागियों को भूमि के साथ उनके संबंधों और इसके भीतर उनकी भूमिका के बारे में गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करती है। लाइब्रेरी के संग्रह में अक्सर पर्यावरणीय विषय उभरते हैं, जो प्रकृति, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के बारे में चिंताओं को दर्शाते हैं। वॉकर उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं जो पारिस्थितिक मुद्दों को संबोधित करती हैं, जो प्राकृतिक दुनिया पर मनुष्यों के प्रभाव पर प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करती हैं। चलने की धीमी, जानबूझकर गति परिदृश्य के साथ एक ध्यानपूर्ण जुड़ाव की अनुमति देती है, जबकि पढ़ने का कार्य इन विषयों के साथ जुड़ाव को गहरा करता है। एक बढ़ रहा हैपुस्तकों का पुरालेख इन वर्षों में, द वॉकिंग लाइब्रेरी ने शीर्षकों का एक व्यापक संग्रह एकत्र किया है। चयन प्रक्रिया अक्सर सहयोगात्मक होती है, जिसमें प्रतिभागी और दर्शक ऐसी पुस्तकों का सुझाव देते हैं जो उनके अनुसार चलने के अनुभव के लिए प्रासंगिक हों। पुस्तकों में कविता और कथा साहित्य से लेकर दर्शन, प्राकृतिक इतिहास और व्यावहारिक मार्गदर्शिकाएँ शामिल हैं। लाइब्रेरी में छपी किताबों के कुछ उदाहरणों में रॉबर्ट मैकफर्लेन की द ओल्ड वेज़: ए जर्नी ऑन फुट, रेबेका सोलनिट की वेंडरलस्ट: ए हिस्ट्री ऑफ़ वॉकिंग और नान शेफर्ड की द लिविंग माउंटेन शामिल हैं। हालाँकि परियोजना किताबों की भूमिका पर जोर देती है, लेकिन यह केवल पढ़ने के बारे में नहीं है। इसके बजाय, द वॉकिंग लाइब्रेरी किताबों को बातचीत और चिंतन के लिए संकेत के रूप में उपयोग करती है। वॉकर एक-दूसरे को ज़ोर से पढ़ सकते हैं या बस उन विचारों पर चर्चा कर सकते हैं जो किताबें प्रेरित करती हैं। इस तरह, परियोजना बौद्धिक आदान-प्रदान के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करने के साथ-साथ संवाद और साझा अनुभवों को बढ़ावा देती है। निष्कर्ष वॉकिंग लाइब्रेरी साहित्य, प्रदर्शन और पर्यावरण जुड़ाव का एक अनूठा मिश्रण है। यह प्रतिभागियों को धीमा होने, ध्यान देने और अपने परिवेश और उनके सामने आने वाले विचारों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलने और पढ़ने को एक साथ लाकर, परियोजना प्रतिबिंब, रचनात्मकता और भूमि और साथी वॉकर दोनों के साथ संबंध के लिए जगह प्रदान करती है। परियोजना लगातार विकसित हो रही है, जिसमें नियमित रूप से नई सैर, किताबें और थीम जोड़ी जा रही हैं। इसके मूल में, द वॉकिंग लाइब्रेरी आंदोलन, विचार और अनंत संभावनाओं का उत्सव है जो तब उत्पन्न होती है जब हम शरीर और दिमाग दोनों के साथ दुनिया के साथ जुड़ते हैं।

निर्माण के अमृतकाल में ग्राम प्रधानों का योगदान सर्वाधिक

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश में 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों की दूरदर्शी सोच ने विकास की नई धारा बहाई है। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों की दूरदर्शी सोच ने विकास की नई धारा बहाई है। इस अभियान में ग्राम प्रधानों को अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

लखनऊ। भारत गांवों का देश है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश उसका प्रतिनिधि राज्य है। यहां के गांवों में जो विकास की ललक है, वह अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों की दूरदर्शी सोच ने विकास की नई धारा बहाई है, और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नवाचारों ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार रूप दिया है।

इस समय को अगर हम 'निर्माण का अमृतकाल' कहें, तो इसमें ग्राम प्रधानों का योगदान सबसे अहम है। देश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और सांस्कृतिक केंद्रों का निर्माण हो रहा है, तो वहीं गांवों में सड़कें, पानी की टंकियां, आवास, शौचालय, और पंचायत भवन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। हमारी पंचायतों के प्रधानों ने इस निर्माण क्रांति में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है और निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं।

देश का नंबर-1 सीमेंट ब्रांड, अल्ट्राटेक, भी इस नव निर्माण का अभिन्न हिस्सा है। 'अल्ट्राटेक-यशस्वी प्रधान' (Ultratech Yashasvi Pradhan) एक ऐसा अभियान है, जिसमें ग्राम पंचायतों के प्रधानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें नई सोच, नई अवधारणाएं, और नवीन परिकल्पनाएं सामने आएंगी।

उत्तर प्रदेश में 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, और प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। ऐसे में, गांवों के समग्र विकास के बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता के बाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था इसी उद्देश्य से अपनाई गई थी, ताकि शासन और सत्ता में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

आज, पंचायती राज व्यवस्था मजबूत और सशक्त दिखाई देती है। ग्राम पंचायतें अब विकास संबंधी फैसले खुद ले रही हैं और आर्थिक संसाधन जुटाने के प्रति भी सक्रिय हैं। 'अल्ट्राटेक-यशस्वी प्रधान' का उद्देश्य इन ग्राम प्रधानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों और उन्नत निर्माणों के लिए सम्मानित करना है।

इस अभियान में ग्राम प्रधानों को अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अभियान के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश के 75 जिलों को 13 केंद्रों में विभाजित किया गया है। हर केंद्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायतों के प्रधान अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे, जिनका मूल्यांकन तीन सदस्यीय ज्यूरी करेगी। प्रत्येक केंद्र से 20 प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा, और उनकी प्रविष्टियों को राज्य स्तर पर चयन के लिए भेजा जाएगा।

राज्य स्तर पर ग्रैंड ज्यूरी द्वारा पूर्व निर्धारित मापदंडों पर आकलन कर 260 प्रतिभागियों में से 20 को 'अल्ट्राटेक-यशस्वी प्रधान' का खिताब दिया जाएगा। इस अभियान में केवल वर्तमान ग्राम प्रधान ही हिस्सा ले सकते हैं, और केवल उनके द्वारा वर्तमान कार्यकाल में शुरू की गई परियोजनाएं ही मान्य होंगी। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2024 के बीच पूरी की गई परियोजनाओं के लिए आवेदन मान्य होगा। आवेदन निःशुल्क है।

कितना खरा है आपके हाथ में रखा सोना, सोनार नहीं आप खुद ही करें आसानी से चेक

आज के समय में खान-पान के साथ गोल्ड में भी मिलावट की जा रही है। वैसे तो बिना मिलावट के कोई गोल्ड ज्वेलरी तैयार नहीं होती है। लेकिन कई सोनार ज्यादा मिलावट करके भी उसे खरा सोने के नाम पर बेचते हैं। ऐसे में लोगों के मन में हमेशा सवाल बना रहता है कि वह जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं वह कितना प्योर है।

नईदिल्ली। फेस्टिव सीजन आ गया है और कुछ दिनों के बाद शादियों का भी सीजन शुरू हो जाएगा। इन दोनों सीजन में खान-पान के साथ गोल्ड (Gold) की काफी डिमांड रहती हैं। सोने की जहां एक तरफ डिमांड बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इसके भाव भी आसमान छू रहे हैं।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (World Gold Council) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच सालों में भारत में गोल्ड की डिमांड 700 से 800 टन रही जो इस साल 900 टन पहुंच सकती हैं। ऐसे में सोने की इतनी पसंद को देखते हुए कई लोग इससे फर्जीवाड़ा भी करते हैं। जी हां, असली सोना बोलकर नकली या फिर मिलावट वाला गोल्ड बेच देते हैं। अब ऐसे में लोगों के मन में हमेशा सवाल बना रहता है कि वह जो सोना खरीद रहे हैं क्या वह खरा यानी असली है या नहीं।

ये बात तो सच है कि कोई भी सोने की ज्वेलरी पुरी तरह से शुद्ध यानी 100 फीसदी प्योर नहीं हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि गोल्ड काफी सॉफ्ट मेटल होता है। ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें मिलावट करना जरूरी होता है। बिना दूसरी धातु की मिलावट किये इसे तैयार नहीं किया जा सकता है।

सोने की ज्वेलरी में कितनी मिलावट हुई है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बता दें कि सोना कितना शुद्ध है इसे मापने का यूनिट कैरेट (K) है। आप इस यूनिट से जान सकते हैं कि आपके पास जो गोल्ड ज्वेलरी है उसमें कितनी मिलावट हुई है।

कैरेट से कैसे मापे सोने की शुद्धता

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) ने सोने की शुद्धता को 6 कैटेगरी में बांटा है। आप जब कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो सोनार आपसे पूछता है कि कौन-से कैरेट में चाहिए। ये कैरेट ही तय करता है कि सोने में कितनी मिलावट हुई हैं। नीचे टेबल से आप समझ सकते हैं कि किस कैरेट का गोल्ड कितना प्योर होता है।

कैरेट	सोने की शुद्धता
14K	58.5%
18K	75%
20K	83.5%
22K	91.6%
23K	95.8%
24K	99.9%

वैसे तो 24K गोल्ड को प्योर माना जाता है पर यह भी केवल 99.9 फीसदी ही शुद्ध होता है। इसका मतलब है कि इसमें भी 0.1 फीसदी की मिलावट की जाती है। अब सवाल है कि आपके पास जो गोल्ड रखा है वह खरा है भी या नहीं, इसकी जांच कैसे करें।

कैसे करें सोने की शुद्धता की जांच

- आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) की वेबसाइट पर जाकर अपने शहर के BIS सेंटर्स चेक करें।
- BIS सेंटर्स में 45 रुपये में गोल्ड की शुद्धता की टेस्टिंग होती है।
- यहां कैरेट मशीन में ज्वेलरी की तीन लेयर में जांच होती है।
- सोना कितना शुद्ध है इसकी जानकारी कैरेट में दी जाती है।

मेकिंग चार्ज पर ऐंठे जाते हैं पैसे

जब भी हम कोई गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते है है तो हमें मेकिंग चार्ज देना पड़ता है। कई ज्वलैरी ब्रांड्स अपने कस्टमर को कहते हैं कि वह बिल दिखाकर ज्वेलरी को एक्सचेंज करवा सकते हैं। जब कस्टमर ज्वैलरी को एक्सचेंज करवाने जाते हैं तो उनसे दोबारा मेकिंग चार्ज लिया जाता है। इस तरह ज्वैलर्स कस्टमर से ज्यादा पैसे लेते हैं। कई बार बिल में मेकिंग चार्ज को वेस्ट चार्ज या डिडक्शन चार्ज के नाम के रूप में दिखाया जाता है।

महंगाई भत्ता बढ़ने से सैलरी में कितना होगा इजाफा, समझिए पूरा कैलकुलेशन

दिवाली से पहले 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा मिला है। उनके महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर में बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिलेगी। आइए जानते हैं कि डीए बढ़ने के बाद सैलरी कितना बढ़कर आएगी और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया। उसने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी का इजाफा किया है। इसका मतलब कि अब केंद्र के सरकारी कर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। आइए जानते हैं कि यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कब से लागू माना जाएगा और इससे सैलरी में कितना इजाफा होगा।

कब से बढ़ेगा डीए

सरकार अमूमन साल में डीए में दो बार बदलाव करती है। एक साल की शुरुआत में, दूसरा पहली छमाही बीतने के बाद। ये 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू माने जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए बढ़ाने पर 16 अक्टूबर 2024 को मुहर लगाई है। लेकिन, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से ही लागू मानी जाएगी। इसका मतलब कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक यानी तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। उन्हें अक्टूबर की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलने लगेगा।

क्या होता है डीए

डीए (डियरनेस अलाउंस) कर्मचारियों की सैलरी का अहम हिस्सा होता है। यह उनके जरूरी खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसके बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होता है। डीए की दरें सरकार तय करती है। इसे मुद्रास्फीति और जीवनशैली के बदलाव के आधार पर समय-समय पर अपडेट भी किया जाता है। इससे कर्मचारियों को अपने जरूरी खर्च को महंगाई के हिसाब से पूरा करने में मदद मिलती है और उनकी जीवनशैली में सुधार होता है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

यह पूरी तरह से कर्मचारी के मौजूदा वेतन पर निर्भर करता है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है, तो 3 फीसदी डीए बढ़ने से उसका मासिक वेतन 1,500 रुपये बढ़ जाएगा। इस हिसाब से अक्टूबर की सैलरी के साथ उसके खाते में 6000 रुपये अतिरिक्त आएंगे। इनमें 4,500 पिछले तीन महीने का एरियर होगा, वहीं 1,500 अक्टूबर का डीए। इसी तरह बेसिक पेंशन के हिसाब से पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा।

कितना बढ़ेगा बोझ

महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ तीन महीने का महंगाई भत्ता एरियर के रूप में मिल जाएगा। सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारी तो 64.89 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। लेकिन खजाने पर सालाना 9,448.35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

महंगाई पर लगेगी लगाम, महाराष्ट्र से सस्ता प्याज ला रही है 'कांडा एक्सप्रेस'

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार अब प्याज की कीमतों को काबू में रखने के लिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए प्याज ला रही है। इससे दिल्ली-एनसीआर में प्याज के भाव कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि रेलवे से प्याज लाना सस्ता है। नासिक से दिल्ली तक एक रेक (56 ट्रकों के बराबर) के परिवहन पर 70 .20 लाख की लागत आती है। वहीं सड़क मार्ग से 84 लाख खर्च होते हैं।

नई दिल्ली। सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वह महाराष्ट्र से दिल्ली तक रेलवे के जरिए 1,600 टन बफर स्टॉक लाएगी। यह पहली दफा है, जब सरकार रसोई के लिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रही है।

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने गुरुवार को बताया कि 'Kanda Express' नामक विशेष रेक महाराष्ट्र के लासलगांव रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 20 अक्टूबर को दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस उपाय से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी, जहां बफर स्टॉक प्याज फिलहाल 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। कई शहरों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं।

खरे ने कहा, ₹यह रेलवे ट्रांसपोर्टेशन एक ऐतिहासिक पहल है। इसी तरह की व्यवस्था लखनऊ, वाराणसी और असम, नागालैंड और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी लागू की जाएगी।' सरकार नुकसान को कम करने के लिए सीलबंद कंटेनर परिवहन के लिए कॉनकॉर्ड के साथ भी बातचीत कर रही है।

निधि खरे ने कहा कि रेलवे से प्याज लाना लागत प्रभावी और कुशल उपाय है। उन्होंने कहा कि नासिक से दिल्ली तक एक रेक (56 ट्रकों के बराबर) के परिवहन पर 70.20 लाख रुपये की लागत आती है। वहीं, सड़क मार्ग से 84 लाख रुपये की लागत आती है। इसका मतलब है कि प्रति रेक 13.80 लाख रुपये की बचत होगी।

सरकार 5 सितंबर से मोबाइल वैन, एनसीसीएफ और नैफेड आउटलेट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मदर डेयरी के सफल आउटलेट और केंद्रीय भंडार सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से रियायती दरों पर बफर स्टॉक प्याज बेच रही है। खुदरा हस्तक्षेप को और मजबूत करने के लिए दिवाली से पहले मोबाइल वैन की संख्या 600 से बढ़ाकर 1,000 की जाएगी।

सचिव ने कहा कि 4.7 लाख टन बफर स्टॉक में से 91,960 टन एनसीसीएफ और नेफेड को आवंटित किया गया है, जबकि 86,000 टन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर सहित विभिन्न राज्यों को भेजा गया है। इन उपायों और महाराष्ट्र से अपेक्षित ताजा फसल की आवक के साथ सरकार को उम्मीद है कि प्याज का दाम काबू में आ जाएगा।

बफर स्टॉक प्याज का औसत खरीद मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम है। सरकार ने कहा कि प्याज के निर्यात मूल्य स्थिर रहे, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाने और शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने के बाद मामूली वृद्धि के बावजूद मात्रा नियंत्रण में है।

एथनाल के बाद अब मेथनाल से आयात बिल कम करने की तैयारी, कार्बन उत्सर्जन के साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी आएगी कमी

परिवहन विशेष न्यूज

पेट्रोलियम के आयात बिल के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए सरकार एथनाल के बाद अब एक अन्य वैकल्पिक ईंधन मेथनाल का बड़े पैमाने पर उत्पादन का इको सिस्टसम तैयार करने में जुट गई है। इस काम में नीति आयोग सरकार की मदद कर रहा है। असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और बीएचईएल (BHEL) के साथ कुछ अन्य कंपनियां मेथनाल का सीमित मात्रा में उत्पादन शुरू कर चुकी है।

नई दिल्ली। पेट्रोलियम के आयात बिल के साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए सरकार एथनाल के बाद अब एक अन्य वैकल्पिक ईंधन मेथनाल का बड़े पैमाने पर उत्पादन का इको सिस्टसम तैयार करने में जुट गई है। इस काम में नीति आयोग सरकार की मदद कर रहा है और जल्द ही सरकार मेथनाल से जुड़े नियामक का फ्रेमवर्क तैयार कर लेगी। अगले कुछ सालों में इजरायल व अन्य देशों की तकनीकी मदद से भारत में कई मेथनाल प्लांट लगाए जाएंगे।

असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और बीएचईएल (BHEL) के साथ कुछ अन्य कंपनियां मेथनाल का सीमित मात्रा में उत्पादन शुरू कर चुकी है। नीति आयोग का मानना है कि मेथनाल अर्थव्यवस्था के विकास से इसके उत्पादन, वितरण व संबंधित सेवाओं से 50 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन होगा। मेथनाल उत्पादन के दौरान निकलने वाली डाई-मिथाइल एथर (डीएमई) को 20 प्रतिशत तक एलपीजी में मिलाने से प्रति एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ता को 50-100 रुपए तक कम दाम पर मिल सकते हैं।

मेथनाल की कीमत उसकी गुणवत्ता और निर्माण के तरीके पर निर्भर करती है, लेकिन औद्योगिक मेथनाल की औसतन कीमत 38-40 रुपए प्रति लीटर बताई जा रही है। डेनमार्क, इजरायल, जापान और चीन जैसे देशों में मेथनाल का प्रयोग वाहनों में धड़ल्ले से हो रहा है। चीन सौ प्रतिशत मेथनाल से चलने वाली सालाना तीन लाख कार, एक-एक लाख बस व ट्रक का निर्माण कर रहा है।

मेथनाल कम कार्बन वाला हाइड्रोजन युक्त फ्यूल है जिसे अधिक धुआं वाले कोयला, कृषि के कचरे, कार्बन डायक्साइड व प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। नीति आयोग के मुताबिक मेथनाल सड़क, रेल और जल तीनों यातायात के साधनों में इस्तेमाल हो सकता है। जेनरेटर सेट, बायलर के अलावा एक सीमा तक एलपीजी में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

गैसोलिन में 15 प्रतिशत मेथनाल मिलाने से कच्चे तेल के आयात बिल में 15 प्रतिशत की कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन 20 प्रतिशत तक कम होगा। भारत में मेथनाल उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए गुरुवार से नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया। आयोग का कहना है कि किर्लोस्कर, अशोक लिलैंड, वोल्वो पेंटा, एनएमआरएल, थर्मेक्स, भेल, एनटीपीसी मेटफ्यूल जैसे भारतीय उद्योग 100 प्रतिशत मेथनाल से चलने वाले ट्रक, बस, हल्के वाहन, जेनरेटर, बायलर, गैस टरबाइन का एप्लीकेशन विकसित कर चुके हैं।

मेथनाल के अंतरराष्ट्रीय मेले में इसकी प्रदर्शनी की जा रही है। बायोमास, कोयला व नवीकरणीय माध्यम से बड़ी मात्रा में मेथनाल का उत्पादन किया जा सकता है। कुछ साल पहले एथनाल उत्पादन और पेट्रोल में उसकी मिलावट को लेकर जोर-शोर से प्रयास शुरू किए गए थे। फिलहाल पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक एथनाल की मिलावट शुरू हो चुकी थी और अगले वित्त वर्ष में यह मिलावट 20 प्रतिशत तक के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। इससे 1016 करोड़ लीटर पेट्रोल की कम खपत होगी और पेट्रोलियम के आयात बिल में चार अरब डॉलर की बचत होगी।

महंगे कच्चे तेल, सोने और केमिकल के आयात ने बढ़ाई महंगाई: एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार आयातित मुद्रास्फीति 13 महीने के उच्चस्तर पर

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आयातित मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोना तेल और रसायनिक उत्पादों के अधिक आयात के चलते आयातित मुद्रास्फीति देश की समग्र मुद्रास्फीति में तेजी से योगदान दे रही है। इस रिपोर्ट में विस्तार से पढ़ें...

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आयातित मुद्रास्फीति सितंबर, 2024 में दो प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। आयातित मुद्रास्फीति किसी देश में आयात होने वाले उत्पादों की उच्च लागत के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में होने वाली वृद्धि है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सोना, तेल और रसायनिक उत्पादों के अधिक आयात के चलते आयातित मुद्रास्फीति देश की समग्र मुद्रास्फीति में तेजी से योगदान दे रही है। आयात में यह वृद्धि विशेष रूप से सोने के आयात के चलते बढ़ी है। सितंबर, 2024 में 10.06 अरब डॉलर का सोना आयात किया गया, जो पिछले साल इसी महीने के 4.94 अरब डॉलर के दोगुने से ज्यादा है।

अकेले अगस्त 2024 में, मूल्य के लिहाज से सोने के आयात में 103.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल-अगस्त 2024-25 की अवधि में आयात में 25.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, मात्रा के लिहाज से, सोने के आयात में मिश्रित रुझान देखा गया, अगस्त में 62.24त्न की वृद्धि हुई, लेकिन अप्रैल-अगस्त की अवधि के दौरान 2.18 टन की गिरावट आई। बढ़ती आयातित मुद्रास्फीति ऐसे समय आई है, जब भारत की समग्र मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में 5.5 प्रतिशत के नौ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि अगस्त में यह 3.65 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि से प्रेरित थी।

एनएसजी स्थापना दिवस विशेष - देश की रक्षा करने वाले योद्धाओं की वीरता और बलिदान को हर भारतीय सदैव गर्व से याद रखेगा : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

परिवहन विशेष न्यूज

कर्तव्य की राह में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले एनएसजी के बहादुर जवानों के अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा को नमन : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

हमारे एनएसजी के बहादुर जवानों के अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि और आभार : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

आगरा, संजय साग़र सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) राइजिंग डे के अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने एनएसजी के सभी कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी और ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले एनएसजी के उन बहादुर जवानों को नमन किया, जिन्होंने कर्तव्य की राह में अपने प्राणों की बलिदान दिया।

श्री खुराना ने कहा,- एनएसजी के वीर सपूतों का समर्पण और अदम्य साहस हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करने वाले इन योद्धाओं की वीरता और बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। हमें उनकी बहादुरी और समर्पण को सलाम करते हैं। हम उनके बलिदान को कभी भूलना नहीं सकते और उनकी सेवाओं के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। एनएसजी के बहादुर जवानों को बारम्बार नमन ! वे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एनएसजी की स्थापना विशेष रूप से आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए की गई थी। एनएसजी के जवान विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं और वे अत्यधिक जोखिम वाले मिशनों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। समय-समय पर एनएसजी के जवानों ने अपने साहसिक अभियानों से देश को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी बहादुरी और समर्पण के कारण ही हमारा देश सुरक्षित है और हम अपने दैनिक जीवन को सामान्य रूप से जी सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा,- एनऐसजी हमारे देश की बेहतरीन कमांडो फोर्स है। इसके एक-एक कमांडों दर्जनों दुश्मनों पर अकेले भारी पड़ते हैं। सिर्फ आतंकियों को मारना ही इनका मुख्य काम नहीं है। ये होस्टेज की स्थिति को संभालते हैं। सीक्रेट मिशन करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक या फिर युद्ध से पहले आसमान हो, जमीन हो या फिर पानी हो कहीं भी ये दुश्मन को मौत दिखा देते हैं। ये मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहते हैं ।एनएसजी ने 'सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा' के अपने आदर्श वाक्य को पूरा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में अद्वितीय विशेषज्ञता दिखाई है। 'सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा' के आदर्श वाक्य पर चलते हुए, एनएसजी ने त्वरित प्रतिक्रिया, सामरिक आश्चर्य, गुप्त संचालन और त्रुटिहीन सटीकता में उल्लेखनीय विशेषज्ञता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को लगातार मजबूत किया है। ये हैं हमारे एनऐसजी कमांडो। देश की रक्षा करने वाले वीर योद्धाओं की वीरता और बलिदान को हर भारतीय सदैव गर्व से याद रखेगा।

नई पीढ़ी को सच्चे देशभक्त डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साहब के विचारों को आदर्श मानना चाहिए : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

नई पीढ़ी को न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी काम करना चाहिए : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

आगरा,संजय साग़र सिंह। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम एक सच्चे देशभक्त और सामाजिक-धार्मिक सद्भाव के प्रतीक थे। वह भारत में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रगति चाहते थे। नई पीढ़ी को सच्चे देशभक्त डॉ. कलाम साहब के विचारों को आदर्श मानना चाहिए और उनके आदर्शों को अपनाकर न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी काम करना चाहिए। उनकी देशभक्ति, शांति, और सद्भाव के संदेश हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। यह विचार वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने भारत के महान वैज्ञानिक को उनके जन्मदिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए व्यक्त किए।

इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने आगे कहा,- शिक्षा डॉ. कलाम साहब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी और उन्होंने भारत के सभी वर्गों की शिक्षा पर जोर दिया। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्हें ₹मिसाइल मैन₹ और ₹जनता के राष्ट्रपति₹ के नाम से जाना जाता है, नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणास्त्रोत हैं। उनका जीवन न केवल विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी विनम्रता, नैतिकता, और समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी उन्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाती है। कलाम साहब का मानना था कि शिक्षा और ज्ञान ही वह साधन हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफल और संतुलित जीवन की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। हमें नयी पीढ़ी को जीवन का एक दृष्टिकोण देना है और उन्हें बुनियादी नैतिक मूल्यों से लैस करना है। उन्होंने सदैव युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने और कड़ी मेहनत के माध्यम से उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ ₹सपने वह नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वह हैं जो हमें सोने नहीं देते₹ इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि वह युवाओं के आत्मविश्वास और उनकी इच्छाशक्ति में अपार विश्वास रखते थे। सामाजिक और धार्मिक सद्भाव की बात करें तो डॉ. कलाम ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज में हर व्यक्ति को उसकी धार्मिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करनी चाहिए। उनके लिए धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय था, लेकिन राष्ट्रीय विकास और समाज की एकता उनके सर्वोच्च मूल्य थे। उन्होंने विविधता में एकता का संदेश दिया और देश के हर नागरिक को समान रूप से देखा।

उन्होंने कहा,- कलाम साहब के मूल विचारों को लागू करने और नई पीढ़ी को उनके पदचिहनों पर चलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भारत के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि डॉ. कलाम साहब के विचारों और अवधारणाओं को अपने जीवन और करियर में शामिल करने का प्रयास करें, ताकि एक ऐसे भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकें, जिसका सपना डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने देखा था। इसलिए हमें उनके विचारों और आदर्शों को अपनाकर न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी काम करना चाहिए। डॉ कलाम साहब के सपने को साकार बनाने के लिये सभी को आगे आना होगा और उनके के सपने को हकीकत में बदलने का प्रयास करना होगा तथा शिक्षा को जीवन का प्रमुख हिस्सा बनाना होगा, तभी बुराइयों से बचा जा सकता है। नयी पीढ़ी देश के भविष्य हैं और एक अच्छी आदत देश में बदलाव ला सकता है। जिस देश के बच्चे सामाजिक, वैचारिक और व्यक्तिगत रूप से शिक्षित होंगे उस देश को आगे बढ़ने से कोइ नहीं रोक सकता। एक जिम्मेदार नागरिक बनें और देश के विकास में अपना योगदान देंने के लिए अच्छी शिक्षा और संस्कार अपनाएं और देश को आगे बढ़ाएं। यही डॉ. कलाम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा, दिवाली के बाद नए पीसीसी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : कांग्रेस को और मजबूत किया जाएगा। 2029 में प्रदेश में सरकार करेगी। इसके साथ ही 21-21 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होगी। इसलिए एआईसीसी ऐसे नेता की तलाश में है जो कांग्रेस को बेहतर बनाए। जो भी जिम्मेदारी लेगा, टीम पहले से ज्यादा कार्यक्रम करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि, नई प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष के नाम की घोषणा दिवाली के बाद की जाएगी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सताश सिंह सलूजा ने कहा ।इसी तरह, पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंचानन कानूनगो ने तर्क दिया है कि ओडिशा कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस प्रमुख ने हरियाणा चुनाव के बाद इस्तीफा दे दिया था। ओडिशा में भले ही कांग्रेस पिछले 24 साल से सत्ता से दूर है, लेकिन हाईकमान को इसकी भनक तक नहीं लगी है। पीसीसी अध्यक्ष और अन्य प्रमुख पद महीनों से नहीं भरे गए हैं। राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक की सभी कमेटियां भंग कर दी गयी हैं। मुट्ठी भर छात्र और युवा कांग्रेस नेता ही विभिन्न मुद्दों पर सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता सामने नहीं आ रहे हैं। सिर्फ एआईसीसी ही कुछ कार्यक्रम करने को कह रही है।

मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में इमरजेंसी अलर्ट

मुंबई से लंदन जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्रियों को इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज दिया गया। यह मैसेज लैंडिंग नहीं होने की वजह सर्कुलेट किया गया। हालांकि लैंडिंग क्यों नहीं हो रही इसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है। एअर इंडिया की फ्लाइट AI129 7700 ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चक्कर लगी रही है।

दिल्ली। मुंबई से लंदन जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्रियों को इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज दिया गया। यह मैसेज लैंडिंग नहीं होने की वजह सर्कुलेट किया गया। हालांकि, लैंडिंग क्यों नहीं हो रही, इसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है। एअर इंडिया की फ्लाइट AI129 7700 ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चक्कर लगी रही है। फ्लाइट ट्रैकर फ्लाइटरडार24 ने गुरुवार को बताया कि मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट ने ब्रिटेन की राजधानी के ऊपर से आपातकालीन सिग्नल भेजा है। हालांकि, आपातकालीन सिग्नल भेजे जाने का कारण पता नहीं चल पाया है।

रिश्ते : सहेज लो-समेट लो

आज-कल के रिश्तों में बस यही बचा है।
ये मिक्चर, ये चिप्स और एक कप चाय।
अगर कहीं किसी जगह मिलीं है काफी,
फिर भी कहीं रह जाती सारी बातें बाकी।
और क्या? सब ठीक है, बाकी अच्छा है?
ये देख़ो यहीं पर राखी का धागा कच्चा है।
दिल में छुपाकर रखा है बाकी जो बचा है,
प्रेम, प्यार, स्नेह और आत्मीयता सब कुछ,
किसी गठरी में बांध के कहीं दूर ही रखा है।
बस, मत पूछो बेरोजगारों से उनकी व्यथाएं।
सुन लो सब हो जाएगा का राग और फाँग।
कैसे! कोई बता भी पाएगा, चुप हो जाएगा।
आज न जाने कैसी रंगत इन रिश्ते में आई है।
साथ में दस लोग बैठे हैं फिर भी ये तन्हाई है।
ढूंढ के लाओ उन रिश्तो को जो पूछा करते थे,
अरे बेटा, तुम्हें कोई और परेशानी तो नहीं है!
ये दुखती हुई रग अपनी है बेगानी तो नहीं है।
हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है।
ये अनूठे रिश्ते कोई राई का पहाड़ तो नहीं है।
अभी-भी इनको हाथों में सहेज लो-समेट लो।
इस प्यार को भर लो यह कोई व्यापार नहीं है।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)

जम्मू-कश्मीर के नये वजीरे ए आला व चुनौतियां....

हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

जम्मू कश्मीर की नई सरकार के मुखिया अमर अब्दुल्ला पहले भी सत्ता समीकरण में अनुभवी राजनीतिक खिलाड़ी रहे हैं। पहले और अब में जम्मू-कश्मीर राज्य में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गया है।अब वह केन्द्र शासित राज्य बन चुका है और जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास भी बड चुका है जनमानस का इसलिए जनता जनार्दन बन गई है। पहले राजनीति की रोटी सेंकी जा रही थी पर अब शह वह मात का खेल बंद हो चुका है। दुसरी और आतंक वह उनको पनाह देने वालों के हौंसले पस्त हो चुकें हैं। केन्द्र सरकार की शक्ति सेना के बुलंद इरादे व देशसेवा के आगे आंतकवादी संगठन के सारे मिशन फैल हों चुके हैं। वक्त व समय दोनों बदल गया है अब वक्त की बागडोर जनता के पास है समय का साथ जनमानस के साथ है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नये वज़ीर ए आला को केन्द्र सरकार व राज्य में समन्वय के साथ सत्ता चलनी होगी । हमेशा से जम्मू कश्मीर ने विकसित भारत की स्वर्णिम इबादत लिखी है। पर इस चुनाव में स्थानीय दलों ने व कांग्रेस ने सहयोगी के साथ सहयोग प्रचार में किया व भाजपा को वह सत्ता में आने से रोक लिया है पर प्रचार में धारा 370 को फिर लागू करने का वादा कर के अमर अब्दुल्ला व उनकी पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है। सही मायने में 370 हटाये जाने के बाद राज्य की जनता का सुख चैन व जीवन में छाया अंधेरा दूर हुआ है और खुशहाली आई है। विकास की बहुत सारी मूल जरूरत तो केन्द्र की मोदी सरकार ने पूरी कर दी है और वह निरंतर कार्य जारी है। इसलिए राज्य की नई सरकार को केन्द्र के साथ सहयोग के बल पर सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। इतने वर्षों बाद जो लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में अपनी पहचान बना रहा है नये मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला जी को भी अपनी पहचान अच्छे शासक की बनानीं होगी। पहले अपने आप में जम्मू-कश्मीर परेशान था आगे कोई रास्ता नजर नहीं आता था वहीं पड़ोसी दुश्मन पकिस्तान अपनी नापाक इरादों से वह के लोगों को मकड़जाल में घेरे रखता था। अब ना वह अंधेरा है और ना वह पत्थरबाज। नई सुबह नई उम्मीद लाई है कश्मीर की वादियों में अमन-चैन शांति कायम है और लाल चौक पर भारत की पहचान हमारा स्वाभिमान तिरंगा शान से लहराया रहा है। इन सभी बातों पर वज़ीर ए आला को गंभीरता से विचार कर चुनौतियां से दो दो हाथ कर सोच समझकर सत्ता चलानीं चहिए। अब परिस्थिति बदल चुकी है जो अच्छा काम करेगा वही शासन करेगा। जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों के लिए रोजगार के समाधान युवा पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के अवसर और पर्यटन क्षेत्र में विकास कार्य और सुविधाएं उपलब्ध करना उन क्षेत्रों को आकर्षित बनाने हेतु प्रचार प्रसार करना राज्य की नई सरकार की एक तरह से चुनौती है। रोजगार के संसाधन खेती किसानी सेवफल के बगीचों को बचाने हेतु व पर्यटन के साथ फिल्म इंडस्ट्री व टेलीविजन चैनल व निर्माता निर्देशक को आमंत्रित करना होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर की सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुकी है यह की फिजा में अब शांति है। लोकतंत्र की मजबूत व्यवस्था हिलोरें ले रही है। ऐसे समय मिलजुल जम्मू कश्मीर प्रदेश को सबसे अच्छा प्रदेश बनने प्रयत्न करना प्रदेश के मुखिया का काम है।

चुतराराम ने तामीलनाडु पॉन ब्रोकर ऐवम ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी तेजानन्द महाराज को मोबाइल फोन भेंट किया

बेगंलुरु: गुरुवार चुतराराम परीहार बेंगलूर ने अपने परिवार कि तरफ सु श्री लिलडीया भेरुजी आईमाताजी सोऽहम आश्रम पेरीयपालीयम के सचांलक स्वामी तेजानन्द के लिए मोबाइल फोन भेजने के लिए भामाशाह चुतराराम परीहार वह उनके पुरे परिवार का आभार वह हार्दिक बधाई व उज्जवल भविष्य की शुभमगंल कामनाएं दी।

श्री आईजी सेवा संघ में सम्मान समारोह कार्यक्रम सम्पन्न

हैदराबाद : कीसरा बंडलागुड़ा चिरीयाला स्थित श्री आईजी सेवा संघ में काग व गेहलोत परिवार द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीरवी समाज पारसीगुटा बडेर शिक्षा समिति अध्यक्ष लाबुराम पंवार, श्री आईजी गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, श्री आईजी गौशाला सलाहकार व पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल मुलेवा, सीरवी समाज पारसीगुटा बडेर सदस्य चेनाराम पंवार, पुनाराम हाम्बड़, कन्हैयालाल परिहार, भींयाराम परिहार, भानाराम, केसाराम सेपटा, लक्ष्मणराम काग, धर्माराम गेहलोत , गौतम गहलोत, गोमाराम काग, ऊर्जाराम गेहलोत, चुन्नीलाल राठौड़, भंवरलाल राठौड़, नेमाराम राठौड़, गोपाराम मुलेवा, रमेश परिहार, मांगीलाल परिहारिया व अन्य उपस्थित रहे

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023